समाचार एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।

पीतम सिंह यादव
9999164275

नई दिल्ली एवं गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित,लखनऊ,गाजियाबाद,मुजफ्फरनगर,मेरठ,हापुड़,बुलन्दशहर,बागपत,फरीदाबाद में एक साथ प्रसारित

दैनिक साांई मीडिया

विश्वास का प्रतीक

वर्ष : 16 अंक : 98 | गौतमबुद्धनगर संस्करण, मंगलवार, 8 अप्रैल 2025 | पेज: 8 | मूल्य : 2 रूपये

आम आदमी को बड़ा झटका, LPG गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढोत्तरी

नई दिल्ली। केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि वितरण कंपनियों ने रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य उपयोगकताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी और उज्ज्वला योजना के तहत उपयोगकताओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एलपीजी के प्रति सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 500 से बढ़कर यह 550 (पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए) हो जाएगा और अन्य के लिए यह 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगा। यह एक ऐसा कदम है जिसकी हम आगे चलकर समीक्षा

करेंगे। हम हर 2-3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करते हैं। इसलिए, आपने जो उत्पाद शुल्क में वृद्धि देखी है, उसका असर पेट्रोल और डीजल पर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। उस उत्पाद शुल्क वृद्धि का उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों को 43,000 करोड़ रुपये की भरपाई करना है, जो उन्हें गैस के हिस्से पर हुए नुकसान के रूप में हुआ है।
राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, ह्लपीएसयू तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।ह्व
आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जनहित में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत बढ़ा हुआ शुल्क लगाया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई उत्पादों के आयात पर अभूतपूर्व टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

इस्लाम ही नहीं, संविधान को भी लहूलुहान करने वाला

- वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त,करेगा प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद में पास हुए हालिया वक्फ संशोधनों को इस्लाम, शरीअत, धार्मिक और संस्कृति

की आजादी के साथ-साथ देश के सेक्युलर ढांचे पर एक बड़ा हमला बताया है। बोर्ड का कहना है कि इन संशोधनों से सिर्फ मुस्लिम समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी पर चोट नहीं की गई, बल्कि भारतीय संविधान की आत्मा को भी लहूलुहान किया गया है।

श्रीलंका में भारत का मास्टरस्ट्रोक कर दिया 'खेला'

- चीन की चाल करेगा नाकाम यूएई संग मिलाया हाथ

कोलंबो (एजेंसी)। भारत ने एक बार फिर इंडियन ओशन में अपना कूटनीतिक खेल दिखाया है। इस बार श्रीलंका में चीन की पकड़ को कमजोर करने के लिए भारत ने मास्टरस्ट्रोक चला है।

दलअसल श्रीलंका के त्रिंकोमाली शहर में भारत, यूएई और श्रीलंका के बीच एक बड़े ऊर्जा हब को बनाने का ऐलान हुआ है। यह कदम न सिर्फ तीन देशों के आपसी सहयोग को मजबूती देगा बल्कि चीन की अरबों डॉलर की परियोजनाओं को चुनौती भी देगा।

किसान नेता डल्लेवाल का 131 दिन बाद अनशन खत्म

- फतेहगढ़ साहिब में किसान महापंचायत में ऐलान,बोले-किसानों की अपील पर किया

खन्ना (एजेंसी)। संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन पॉलिटिकल) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिन बाद आमरण अनशन खत्म कर दिया है।

रविवार को फतेहगढ़ साहिब की सरहिंद अनाज मंडी में किसान महापंचायत में उन्होंने इसका ऐलान किया। डल्लेवाल ने कहा कि किसानों की मांग पर आमरण अनशन खत्म किया है। काफी समय से किसान उन्हें अनशन तोड़ने की अपील कर रहे थे। डल्लेवाल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समेत अन्य मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 को अनशन शुरू किया था।

Trump Tariff: क्या भारत अमेरिका के टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करेगा?

बाजार में मंदी के बावजूद जवाबी शुल्क लगाने से परहेज करेगा हिंदुस्तान

नई दिल्ली। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों में एक नया मोड़ आया है। अमेरिका ने भारत समेत

ट्रंप के इस कदम ने वैश्विक बाजारों के साथ-साथ दलाल स्ट्रीट को भी हिलाकर रख दिया है, बुधवार से सेंसेक्स में 1.6% की गिरावट आई है।

कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए 26 % टैरिफ के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अब ताजा रिपोर्ट बता रही है कि बाजार में मंदी के बावजूद भारत अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने से परहेज करेगा।
एक सरकारी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका से निर्यात पर 26% शुल्क लगाए जाने के बाद भारत द्वारा अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को

जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना नहीं है।
ट्रंप के इस कदम ने वैश्विक बाजारों के साथ-साथ दलाल स्ट्रीट को भी हिलाकर रख दिया है, बुधवार से सेंसेक्स में 1.6% की गिरावट आई है। अधिकारी ने कहा कि सरकार पिछले सप्ताह ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के एक प्रमुख खंड पर भरोसा कर रही है, जो उन देशों को राहत प्रदान करता है जो "गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम" उठाते हैं। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारत इस तथ्य से राहत महसूस कर रहा है कि वह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने वाले पहले देशों में से एक था। इसके एशियाई समकक्ष, जैसे चीन (34%), वियतनाम (46%), और इंडोनेशिया (32%), उच्च शुल्कों से प्रभावित हुए हैंkचीन ने कहा कि वह 10 अप्रैल से अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 34% टैरिफ लगाएगा, जबकि इंडोनेशिया ने कहा कि वह जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। चीन के लिए एक उभरता हुआ विनिर्माण और निर्यात विकल्प वियतनाम संभावित व्यापार सौदे में अपने टैरिफ को शून्य करने पर सहमत हो गया है। पिछले सप्ताह, ट्रम्प ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "महान मित्र" कहा था। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि सेमीकं डक्टर, तांबा और फार्मास्यूटिकल्स को अमेरिकी टैरिफ से छूट दी गई है। भारत अमेरिका में लगभग आधी जेनेरिक दवाइयों की आपूर्ति करता है। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, रत्न और आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात प्रभावित हो सकता है।
जबकि भारत टैरिफ पर अपनी प्रतिक्रिया में सतर्क रहा है, विपक्ष ने पीएम मोदी और ट्रम्प के बीच "मित्रता" के बावजूद राहत पाने में विफल रहने के लिए सरकार पर हमला किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि टैरिफ अर्थव्यवस्था को "पूरी तरह से तबाह" कर देंगे। अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में काफी प्रगति हुई है। पिछले महीने, दोनों देशों ने बीटीए के लिए संदर्भ की शर्तों पर सहमति व्यक्त की। भारत ने हार्ले-डेविडसन बाइक और बॉर्बन व्हिस्की पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 40% करके ट्रम्प को जीतने की कोशिश की है। इसने डिजिटल सेवाओं पर कर भी हटा दिया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 'गूगल टैक्स' के नाम से जाना जाता है, जिसका असर अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों पर पड़ता था।

पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, नोटिफिकेशन जारी

जनता पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

नई दिल्ली। राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, ह्लपीएसयू तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जनहित में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत बढ़ा हुआ शुल्क लगाया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई उत्पादों के आयात पर अभूतपूर्व टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

अमित शाह ने कठुआ में बीएसएफ जवानों की बहादुरी को सराहा

शहीदों के परिजनों से की मुलाकात

जम्मू-कश्मीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कठुआ सीमा चौकी का दौरा किया, जहां उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर आए शाह ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ सीमा सुरक्षा को आधुनिक बनाने के महत्व पर जोर दिया। कठुआ में ह्यविनयह्न सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से बात करते हुए

शाह ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
गृह मंत्री ने बीएसएफ की उनके अथक परिश्रम, खासकर कठिन परिस्थितियों में, की प्रशंसा की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि भूमिगत सीमापार सुरंगों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपने (सीमा सुरक्षा बलों ने) विपरीत परिस्थितियों में देश की सेवा की है। हम जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं, उससे आपको क्रिसी भी घटना की स्थिति में सूचना प्राप्त करने और प्रतिक्रिया करने में मदद मिलेगी और सीमा सुरक्षा मजबूत होगी।
शाह की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि देना था, जिनके नाम पर कठुआ सीमा चौकी का नाम रखा गया है। 15 जनवरी, 2019 को पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा बीएसएफ पार्टी पर की गई गोलीबारी में प्रसाद की दुखद मौत हो गई थी। उस समय तटबंध परियोजना की निगरानी कर रहे अधिकारी ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उन्हें घातक चोटें आईं। शाह ने शहीद अधिकारी के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की और प्रसाद की बहादुरी और अंतिम बलिदान को श्रद्धांजलि दी।
शाह ने क्षेत्र में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों से भी मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने इन शहीदों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की पेशकश की। यह कदम देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों के परिवारों का समर्थन करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। अमित शाह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वाले 11 शहीदों के परिवारों से मुलाकात की।

दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के समक्ष 26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, तीन इनामी नक्सली भी शामिल

छत्तीसगढ़ : दंतेवाड़ा जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों के सामने 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें तीन इनामी नक्सली भी शामिल हैं। राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के सरकार के प्रयासों के बीच यह कदम उठाया गया है। हाल के महीनों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ों की एक श्रृंखला देखने को मिली है, जिसमें कई उग्रवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि, एक सकारात्मक बदलाव यह भी देखने को मिला है कि अब कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय के अनुसार, नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और खोखली और अमानवीय माओवादी विचारधारा से अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने जंगल में रहने की कठिनाइयों और प्रतिबंधित संगठन के भीतर आंतरिक संघर्षों को हथियार डालने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली माओवादियों के जनमिलिशिया, क्रांतिकारी पार्टी समिति (आरपीसी) और जनताना सरकार विंग और दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन (डीएकेएमएस) और चेतना नाट्य मंडली (सीएनएम) जैसी उनकी अग्रणी इकाइयों से संबंधित थे। अधिकारियों के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से राजेश कश्यप, जो आमदई क्षेत्र के जनमिलिशिया कमांडर के रूप में काम करता था, पर 3 लाख रुपये का इनाम था। जनताना सरकार दस्ते के प्रमुख कोसा माडवी पर 1 लाख रुपये का इनाम था, जबकि सीएनएम (चेतना नाट्य मंच) के सदस्य छोटू कुंजाम पर 50,000 रुपये का इनाम था। इसके साथ ही कुल 953 नक्सलियों, जिनमें 224 नकद पुरस्कार शामिल हैं, ने अब दंतेवाड़ा में 'लोन वरार्टू' अभियान के तहत हथियार छोड़ दिए हैं, जो जून 2020 में विद्रोहियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

देश में 'यूसीसी' की अब सख्त जरूरत

- सरकार से बोला हाई कोर्ट-कानून बनाओ

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक हाई कोर्ट ने संसद और राज्य विधानसभाओं से अनुरोध किया है कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर कानून बनाने की कोशिश करें। इससे भारत के संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांतों के उद्देश्य को सही मायने में हासिल किया जा सके। जस्टिस हंचते संजीव कुमार की अध्यक्षता वाली सिंगल जज की बेंच ने एक मृतक मुस्लिम महिला शहनाज बेगम के भाई-बहनों और पति के बीच संपत्ति विवाद से जुड़ी एक दीवानी अपील पर फैसला सुनाते हुए यह सिफारिश की। कोर्ट ने कहा,देश को व्यक्तिगत कानूनों और धर्म के संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, तभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्राप्त होगा। इस मामले ने व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों द्वारा शासित

उत्तराधिकार कानूनों और लैंगिक न्याय पर सवाल उठाए। जस्टिस कुमार ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का अधिनियमन प्रस्तावना में निहित आदर्शों-अर्थात न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता को पूरा करेगा। कोर्ट ने कहा, देश को व्यक्तिगत कानूनों और धर्म के संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, तभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्राप्त होगा।

एक राष्ट्र, एक चुनाव से ही देश में आएगी राजनीतिक स्थिरता, विकास को मिलेगी गति- सीएम योगी

अपनी आंतरिक कलह और टूट से बचने के लिए कांग्रेस ने देश को भटकाया और राजनीतिक अस्थिरता पैदा की- सीएम योगी

बार-बार चुनाव जनता पर बनता है अनावश्यक बोझ, भ्रष्टाचार को देता है बढ़ावा- मुख्यमंत्री

समिति की सिफारिशों और जनजागरण के जरिए 2034 तक देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव संभव- मुख्यमंत्री

माफिया और गुंडागर्दी ने प्रदेश के विकास को बाधित किया, जिससे पहचान का संकट खड़ा हो गया- योगी

विपक्ष ने महाकुंभ का दुष्प्रचार किया, लेकिन जनता ने नकार दिया- योगी

सीएम योगी ने लोगों से वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में जनजागरण की अपील की

साईं मीडिया ब्यूरो

लखनऊ, 7 अप्रैल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी पंसद का जनप्रतिनिधि चुनना जनता का अधिकार है, लेकिन बार-बार चुनाव जनता पर अनावश्यक बोझ डालता है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक अस्थिरता को न सिर्फ जन्म देता है बल्कि देश के अंदर विकास की संभावनाओं को बाधित करता है और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता कभी भी देश को संप्रभुता संपन्न और विकसित देश की परिकल्पना को साकार करने में सहभागी नहीं बन सकती है। बार-बार का इलेक्शन देश और प्रदेश की जीडीपी को प्रभावित करता है। विकास के लिए चालू योजनाओं में बैरियर का काम करता है और लोकतंत्र के प्रति लोगों के आकर्षण को भी कम करता है। सीएम योगी सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक राष्ट्र-एक चुनाव अभियान के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्वन नेशन वन इलेक्शनह्ल विजन को साकार करने की आवश्यकता है, जो 2019 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण के दौरान घोषित हुआ था। सीएम योगी ने कहा कि यह विचार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई का भी था, जिन्होंने राजनीतिक स्थिरता को सुशासन, सुरक्षा और विकास की पहली शर्त माना था।

सीएम योगी ने कहा कि 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी टूट के बाद यह प्रथा समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि 1967 के बाद सरकारें भंग की गईं, राष्ट्रपति शासन लगा और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को भटकाया। 1980 के दशक में भी यह मुद्दा उठा, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों और जनजागरण के जरिए इसे 2034 तक लागू करने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि विधानसभाओं के कार्यकाल को समायोजित कर एक साथ चुनाव संभव हों, जिससे 3.5 से 4.5 लाख करोड़ रुपये के सालाना खर्च को विकास कार्यों में लगाया जा सके।

सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, खासकर 2017 से पहले की स्थिति को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलती थी, जो कानून और संवैधानिक प्रोटोकॉल की परवाह नहीं करती थी। संसाधनों पर लूट और माफियाराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन गया था। उन्होंने कहा कि इस अस्थिरता ने प्रदेश को देश की सातवीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचा दिया, जबकि 1947 में यह राष्ट्रीय औसत के बराबर थी। सीएम योगी ने कहा कि माफिया और गुंडागर्दी ने प्रदेश के विकास को बाधित किया, और पहचान का संकट खड़ा हो गया था।

सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश भी इसी अस्थिरता का शिकार था, जिससे विश्वास और पहचान का संकट पैदा हुआ। लेकिन आज भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और उत्तर प्रदेश 8 साल में प्रगति के पथ पर है। यह राजनीतिक स्थिरता का परिणाम है। उन्होंने माफिया और अराजकता को बढ़ावा देने वाले तत्वों को ह्यलोकतंत्र विरोधीह्ल बताते हुए कहा कि ये लोग बार-बार चुनाव से फायदा उठाते हैं।

सीएम ने महाकुंभ 2025 का जिक्र कर अपनी सरकार की उपलब्धियों को सभी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 13 से 26 जनवरी 2025 के बीच प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ, जो हजारों साल की हमारी विरासत का प्रतीक है, ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव बन गया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने इस आयोजन को उपेक्षित रखा। 2007 और 2013 में अव्यवस्था और गंदगी थी। योगी ने बताया कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अरुणाचल, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक के लोग आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, लेकिन जनता ने इसे नकार दिया। लोग पैदल चलकर त्रिवेणी स्नान के लिए आए।

सीएम योगी ने लोगों से ह्वन नेशन वन इलेक्शनह्ल के समर्थन में जनजागरण की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष दुष्प्रचार करेगा, लेकिन हमें जवाब देना चाहिए कि ह्यदेश हमारा है, विकास हमारा है, राजनीतिक स्थिरता हमारी जरूरत हैह्ल उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बढ़ानी होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि बार-बार चुनाव से 3.5 से 4.5 लाख करोड़ रुपये का बोझ जनता पर पड़ता है, जो विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। 2034 तक एक साथ चुनाव का लक्ष्य है, जिसमें कार्यकाल समायोजन और मध्यावधि चुनावों पर रोक होगी।

इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, एमएलसी अनूप गुप्ता, महेन्द्र सिंह, अवनीश कुमार समेत कई गणमान्य मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई खेल संस्कृति को दिया बढ़ावा: सीएम योगी

प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- सीएम बोले, पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से 500 से अधिक खिलाड़ियों की अबतक की जा चुकी है भर्ती

- सीएम ने राजधानी में हो रहे क्लस्टर समारोह के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का जताया आभार

- 65,000 से अधिक महिला और पुरुष मंगल दल को गांव-गांव में वितरित की गई स्पोर्ट्स किट

- प्रदेश में 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हाल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम और दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया गया निर्माण

साईं मीडिया ब्यूरो

लखनऊ, 7 अप्रैलः प्राचीन काल से ही खेलकूद की गतिविधियां भारत के जीवन का हिस्सा रही हैं। ऐसे में भारतीय मनीषियों ने भी कहा है कि धर्म के जितने भी साधन हैं, उसकी पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। अगर आप सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ भारत चाहिए। इसके लिए खेलकूद की गतिविधियों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने के दिशा में प्रयास होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के साथ देश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रत्येक जनपद में सांई के केंद्र इस बात के उदाहरण हैं। इन सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके ही देश में ऑल इंडिया पुलिस के टूनार्मेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि आज से अगले 5 दिनों तक ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर- 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी में होने जा रहा है। इसमें देशभर के केंद्रीय बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिसबलों से जुड़े हुई 75 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता में 1,341 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें 336 महिला खिलाड़ी भी हिस्सेदार बनने जा रही हैं। इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। यें बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-2025 के उद्घाटन समारोह में कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार किसी प्रतियोगिता में 75 से अधिक टीमें और 1,341 खिलाड़ी एक साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में देश भर से पूर्वोत्तर के सुदूर मणिपुर से लेकर करके केरल और तमिलनाडु की टीम, जम्मू कश्मीर से लेकर करके तेलंगाना की टीम, वेस्ट बंगाल की टीमें आयोजन का हिस्सा बन करके इसे नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगी। प्रतियोगिता एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए देश ने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है। उसी का परिणाम है कि खेलकूद भी व्यक्ति के जीवन को सजाने और संवारने का माध्यम बन रहा है। सरकार ने प्रदेश में खेल नीति लागू की है। पिछले 5 वर्षों में अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने 500 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित की है। वहीं सरकार द्वारा मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती के माध्यम से 500 से अधिक खिलाड़ियों को अभी तक अलग-अलग पदों पर भर्ती किया है। सीएम ने कहा कि खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 65,000 से अधिक महिला और पुरुष मंगल दल को स्पोर्ट्स किट गांव-गांव में वितरित की गयी है। उत्तर प्रदेश में 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हाल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 13 कुश्ती हॉल, 38 तरल ताल, 47 अत्याधुनिक जिम सेंटर, 20 सिंथेटिक ट्रेनिंग टेनिस कोर्ट ,16 छात्रावास भवन, 8 शूटिंग रेंज, 14 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 4 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और दो जीरो हॉल, 12 वेटलिफ्टिंग हॉल, 2 वॉलीबॉल हाल और 19 डॉरमेट्री आदि का विकास किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 18 जनपदों में खेल विभाग द्वारा संचालित 44 स्पोर्ट्स हॉस्टल में 16 खेलों के लिए 740 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में तीन स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, लखनऊ और इटावा में पहले से ही संचालित हैं, जिनमें खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ कुशल प्रशिक्षकों को भी तैनात किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एस्ट्रो टर्फ लगाया गया है। स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल के खिलाड़ियों की डाइट को बढ़ाया गया है। स्पोर्ट्स हॉस्टल में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए 50 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1,50,000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर नियुक्त किया गया है। वाराणसी में प्रदेश के तीसरे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाराणसी के सिगरा में डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 287 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नये इनडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। यहां बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग समेत 20 से अधिक इनडोर खेलों की सुविधा प्रदान की गई है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहां इसी सत्र से पढ़ाई शुरू होने जा रही है। हर जनपद में एक जनपद एक खेल योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 20,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। राज्य स्तर के पूर्व खिलाड़ियों को 4,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपये और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सीएम ने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष वर्ग में और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला वर्ग में प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा एशियाई गेम्स में प्रदेश के पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की भी व्यवस्था की गयी है। इसमें ओलंपिक में एकल गेम में प्रदेश के खिलाड़ी को स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर दो करोड़ रुपए के पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है। ओलंपिक गेम के टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर दो करोड़ तथा कांस्य पदक पर एक करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर दो करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए का पुरस्कार, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर डेढ़ करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिये जा रहे हैं।

सीएम ने कहा कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ी को 10 लाख रुपए, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभा के लिए 5-5 लाख रुपए प्रदान किये जा रहे हैं। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से पुलिस विभाग में सीधी नियुक्ति दी जा रही है। सरकार ने हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय को पुलिस उपाधीक्षक, क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, एथेलेटिक खिलाड़ी पारूल चौधरी, शूटिंग के खिलाड़ी अखिल स्वर्ण और कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन देशवाल को डिप्टी एसपी का पद प्रदान किया गया है। जूडो खिलाड़ी विजय कुमार यादव, कुश्ती खिलाड़ी दिव्या कांकरान को नायब तहसीलदार, टेनिस खिलाड़ी अर्जुन सिंह को यात्री कर अधिकारी और एथलीट खिलाड़ी प्राची, खिलाड़ी पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण और प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी है। हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। अब तक पुलिस विभाग में 2 लाख 10 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा कुशल खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति के नियमों को आसान किया गया है। वहीं 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में एस्ट्रो टर्फ और सिंथेटिक एथलेटिक ग्राउंड का पुनर्निर्माण कराया गया है। पीएसी लखनऊ में 150 खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स हॉस्टल, 10वीं और 12वीं पीएसी बाराबंकी में एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड का निर्माण कराया गया है। बाराबंकी में ही 150 खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी गाजियाबाद में स्पोट्स काम्प्लेक्स का निर्माण भी कराया गया है। 47वीं वाहिनी गाजियाबाद में कबड्डी ग्राउंड और तीन सेट का निर्माण भी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस स्पॉट और कंट्रोल बोर्ड को खिलाड़ियों के खेल विकास के लिए 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इस पर वर्तमान में कार्य चल रहा है।महाकुम्भ में आने वाले हर व्यक्ति ने पुलिस के व्यवहार और कार्य कुशलता की सराहना की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां पर हम बास्केटबॉल और हैंडबॉल क्लस्टर का एक मिनी कुम्भ देख रहे हैं, लेकिन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में पूरे देश और पूरी दुनिया ने प्रयागराज की धरती पर महाकुम्भ 2025 के दर्शन किए थे। महाकुम्भ में आने वाले हर व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के व्यवहार और कार्य कुशलता की सराहना ही। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और एडीजी पीएसी सुजीत पांडेय आदि मौजूद रहे।

जीवनोपयोगी तकनीकी का किफायती मॉडल विकसित करें प्रौद्योगिकी संस्थान : मुख्यमंत्री

ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सस्ती और टिकाऊ तकनीकी जरूरी : सीएम योगी

सांई मीडिया ब्यूरो

गोरखपुर, 7 अप्रैल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी जिम्मेदारी को परिसर तक सीमित नहीं रख सकता। समाज और राष्ट्र के प्रति भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आज तकनीकी से मानव जीवन में काफी आसानी हो रही है लेकिन महंगी तकनीकी का इस्तेमाल कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे में प्रौद्योगिकी संस्थानों को जीवनोपयोगी तकनीकी का किफायती और टिकाऊं मॉडल विकसित करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आना होगा।

सीएम योगी सोमवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में 91 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 13 विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास तथा शिक्षकों-शोधार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंचीय कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री ने चार सीएनजी बसों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तकनीकी महंगी होगी तो आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी। आज जन सरोकार से जुड़े विषयों जैसे आवास, पर्यावरण, स्वच्छता आदि के लिए सस्ती और टिकाऊ तकनीकी समय की मांग है। ऐसी तकनीकी आनी चाहिए जिससे आम जन सस्ता और टिकाऊ आवास बना सकें। एक उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने सवाल किया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये देती है, क्या हम ऐसी तकनीकी अपने स्तर पर विकसित कर सकते हैं कि इसी धनराशि के अंदर ही गरीब अपना मकान बना सके? यह मकान नौ माह की बजाय तीन माह में ही बन सके? इसी तरह उन्होंने ईंट भट्ठे के कारण भूमि की उर्वरता और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा कि ईंट का विकल्प खोजने के लिए नई तकनीकी खोजने तथा सॉलिड-लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए देसी पद्धतियों में समय के अनुरूप नवाचार करने की अपेक्षा जताई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा की सस्ती और टिकाऊ तकनीकी की आवश्यकता इसलिए भी है कि सरकार कोई भी पैसा अपने जेब से नहीं देती है। बल्कि यह पैसा समाज के लोगों से ही प्राप्त होता है। सरकार को कर (टैक्स) माध्यम से जो पैसा प्राप्त होता है, उसे बजट बनाकर अलग-अलग विभागों के माध्यम से जनता के ही उपयोग के लिए खर्च किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति तक सस्ती और टिकाऊ तकनीकी की पहुंच आवश्यक है। पर, यह भी ध्यान रखना होगा कि तकनीकी हमसे संचालित हो, हम तकनीकी से संचालित न हों। तकनीकी ने जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है। लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाया है। शासन की सुविधा और शासन द्वारा अपनाई गई तकनीक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके कई प्रमाण हैं। प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था में भी तकनीकी का ही योगदान है। इस व्यवस्था के पहले 2017 में जब एक ही दिन 80 हजार उचित मूल्य वाली दुकानों की जांच की गई तो 30 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ में आए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन को महज 300 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी और मैनुअल व्यवस्था के कारण उसमें में काफी पैसा किराए और बाबू के कट में चला जाता था। अब सरकार ने न केवल पेंशन की राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये मासिक कर दी बल्कि सीधे खाते में रकम ट्रांसफर कर किराए और बाबू के कट से भी मुक्ति दिला दी है। यह तकनीकी का जनहितकारी इस्तेमाल है। सीएम योगी ने पूर्व में पथ प्रकाश के लिए लगे हैलोजन की जगह एलईडी लाइट के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन कम होने और 1000 करोड रुपये की बचत होने को भी तकनीक के जन उपयोगी पक्ष का हिस्सा बताया।

सस्ता और टिकाऊ तकनीकी की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम द्वारा दूषित जल के शोधन के लिए अपनाई गई देसी पद्धति की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि महानगर का दूषित जल राप्ती नदी में सीधे गिरने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम पर भारी भरकम जुमार्ना लगा दिया था। तब नगर निगम के अधिकारियों ने एसटीपी लगाने के लिए 110 करोड रुपये का प्रस्ताव तैयार किया। जब यह प्रस्ताव उनके पास आया तो उन्होंने देशी पद्धति से वॉटर ट्रीटमेंट करने का सुझाव दिया था। इस पद्धति में सिर्फ दस करोड़ रुपये का खर्च आया। इसमें बोल्डर, बड़े और छोटे पत्थर और वनस्पतियों के बीच से होकर गुजरने वाला जल शोधित हो रहा है। गोरखपुर के इस देशी वॉटर ट्रीटमेंट का प्रेजेंटेशन नीति आयोग के सामने भी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पद्धति की सराहना तकनीकी के मामलों में बेहद एग्रेसिव एप्रोच रखने वाले जर्मनी जैसे यूरोपीय देश ने भी की है।

मुख्यमंत्री ने आधुनिक जगत में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों की चर्चा करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग समय की मांग है। उन्होंने कहा कि एआई और रोबोटिक्स से मानव जीवन की तमाम परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने कुछ नगर निकायों की तरफ से सीवर सफाई के लिए रोबोटिक्स के हो रहे इस्तेमाल की चर्चा की। साथ ही या आह्वान किया कि इस रोबोटिक्स के ऐसे मॉडल भी बनने चाहिए जो कम खर्चीले हों, जिससे आमजन भी इसका इस्तेमाल कर सकें।

सीएम योगी ने कहा कि जब हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो भारतीय मनीषा ने पश्चिम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) की बजाय समग्र विकास की परिकल्पना को सामने रखा। हमारा दृष्टिकोण समग्रता को लेकर होता है। सतत विकास में ध्यान किसी एक ही पक्ष पर होता है जबकि समग्र विकास में अलग अलग पक्षों से सबको साथ लेकर चलने की बात अंतर्निहित होती है। यह भारतीय दृष्टि है कि हम समग्रता में विश्वास करते हुए विकास पथ पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने में जुटा हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अंदर शिक्षा और तकनीकी में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम विश्व गुरु कहलाए क्योंकि हम दुनिया मे लीड करते थे। सोलहवीं सदी के पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक थी और यह तब था जब भारत ने बहुत कुछ खाया था। यानी अगर दसवीं सदी तक दुनिया की जीडीपी में आधे से अधिक हिस्सेदारी अकेले भारत की हुआ करती थी। अंग्रेजों ने अपने कालखंड में यहां के संसाधनों को लूट लिया। अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। सीएम ने कहा कि देश के आजाद होने के बाद भी 1947 से लेकर के 2014 तक आते-आते 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत दुनिया की केवल ग्यारहवीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। जबकि पिछले दस वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरेक क्षेत्र में विकास करते हुए देश दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के कालखंड में जब दुनिया के आने का अनेक देश पस्त हो गए थे, तब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने नागरिकों को मुफ्त राशन दे रहा था। मुफ्त में जांच, इलाज और वैक्सीन की सुविधा दे रहा था। एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ता भारत अगले दो वर्ष में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। आज भारत के विकास की दर दुनिया के किसी भी देश से बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत एक बार फिर दुनिया को लीड करने की ओर अग्रसर है।

सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 769 नियुक्त शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि जिस कार्य के लिए उनका चयन हुआ है उस पर हर साबित होना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर जवाब काम करेंगे तो विश्वविद्यालय के हिस्से आई उपलब्धि के हकदार आप भी बनेंगे। यदि विश्वविद्यालय पर कहीं कोई डेंट आएगा तो उसकी भी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। यह दोनों चीज जीवन में समान रूप से चलती हैं। कोई भी सफलता टीमवर्क से ही प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को हासिल राष्ट्रीय, दक्षिण एशिया और एशिया स्तर तक की अच्छी रैंकिंग के लिए शुभकामनाएं दीं। साथ ही यह अपेक्षा भी की कि विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 50 और साउथ एशिया स्तर पर टॉप 100 के अंदर की रैंकिंग हासिल करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो चुनौतियों का सामना करता है वह निखरता है और जो उससे पलायन करता है वह बिखर जाता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि सीएम योगी पूरे प्रदेश की चिंता करते हैं। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी और प्रौद्योगिकी से सक्षम बनाने के लिए वे निरंतर कुछ नया मंथन करते हैं। सांसद ने कहा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है और यह वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नई-नई उपलब्धियां को प्राप्त कर रहा है। यहां विद्यार्थियों के हित में विकास के कई कार्य आगे बढ़ाई जा रहे हैं।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने अपनी संबोधन में मुख्यमंत्री का स्वागत करने के साथ ही विश्वविद्यालय की प्रगति व उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 76 नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी तरीके से की गई है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हुई है। कुलपति ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से विश्वविद्यालय का निरंतर विकास हो रहा है। इसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सतत उन्नयन हो रहा है। इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव सहित कई जनप्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने नवनियुक्त शिक्षकों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर सीएम योगी ने अनुसंधान एवं शोध प्रकाशन के लिए छह शिक्षकों और पांच छात्रों को पुरस्कार एवं तीन शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया मुख्यमंत्री ने।

सरकार का संकल्प, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय : मुख्यमंत्री

जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं 300 लोगों की समस्याएं

अफसरों को दिए निर्देश, त्वरित व संतुष्टिपरक हो समस्याओं का समाधान

सांई मीडिया ब्यूरो

गोरखपुर, 7 अप्रैल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कि किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सुनिश्चित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण उनकी सरकार की विशेष प्राथमिकता है। पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से कराना सुनिश्चित कराएं।

जनता दर्शन के दौरान सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। सबको आश्वस्त किया कि किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्या का समाधान हरहाल में किया जाएगा। सरकार का संकल्प है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं जमीन से जुड़े विवादों में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची थीं। कुछ की शिकायत थी कि दबंग उनकी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीन कब्जाने में पेशेवर प्रवृत्ति वालों को भू माफिया के रूप में चिन्हित कर सख्ती की जाए। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जो नजीर बने। जमीनी विवादों का समाधान तत्परतापूर्वक इस तरह होना चाहिए जिससे पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट दिखे।

जनता दर्शन में प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों को लेकर विवाद संबंधी शिकायतों पर सीएम ने अफसरों से कहा कि सबसे पहले इसमें सभी पक्षों को एकसाथ बैठाकर संवाद करने की जरूरत है। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारकर आशीर्वाद दिया। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और चॉकलेट गिफ्ट कर उन्हें खूब पढ़ने को प्रेरित किया।

सीएम योगी ने मोर को खिलाया केला, बच्चों को दिया चॉकलेट

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोमवार सुबह की दिनचर्या परंपरागत रही। प्रातः काल गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर मत्था टेकने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। गोशाला जाकर मुख्यमंत्री ने गोसेवा की। गोशाला के समीप एक मोर को रोटी और केला खिलाकर उस पर अपना स्नेह लुटाया। मंदिर परिसर का भ्रमण करने के दौरान सीएम योगी की नजर अपने परिजनों

संग आए बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने बच्चों को पास बुला लिया। उनसे हंसी ठिठोली करके खूब प्यार-दुलार किया और चॉकलेट गिफ्ट की। एक नन्हा बच्चा चॉकलेट का रैपर नहीं खोल पा रहा तो मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से रैपर हटाकर उसे खाने को दिया।

योगी सरकार ने यूपी को बनाया डीबीटी और डिजिटल पेमेंट में अग्रणी राज्य

लखनऊ, 7 अप्रैल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत और दूरदर्शी सोच ने यूपी को डिजिटल लेनदेन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) में पूरे देश में अग्रणी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां 2017-18 में राज्य में 122.84 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए थे, वहीं 2024-25 में दिसंबर तक यह आंकड़ा 1024.41 करोड़ तक पहुंच गया। इतने कम समय में इतनी बड़ी छलांग लगाना यूपी की ताकत को दिखाता है। आज यूपी डिजिटल लेनदेन में नंबर वन है और खास बात यह है कि ज्यादातर ट्रांजेक्शन यूपीआई से हो रहे हैं।शहर से लेकर गांव-गांव तक डिजिटल पहुंच

योगी सरकार ने डिजिटल क्रांति को हर घर तक पहुंचाने का सपना सच कर दिखाया है। डिजिटल बैंकिंग को आसान बनाने के साथ-साथ गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई है। लोगों को इसके फायदे समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। राज्य में 20,416 बैंक शाखाएं, 4,00,932 बैंक मित्र और बीसी सखी, 18,747 एटीएम और 4,40,095 बैंकिंग केंद्र काम कर रहे हैं। ये सुविधाएं शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों तक लोगों की मदद कर रही हैं। बैंक मित्र और बीसी सखी जैसे कदमों से महिलाओं को भी रोजगार मिला है और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग आसान हुई है।

डीबीटी से पहुंच रहा सीधा फायदा

योगी आदित्यनाथ का डीबीटी पर खास जोर यूपी की एक और बड़ी कामयाबी है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है, बिना किसी बिचौलिए के। 11 विभागों की 207 योजनाएं इस सिस्टम से चल रही हैं, जिनमें 113 केंद्रीय और 95 राज्य सरकार की योजनाएं शामिल हैं। 2024-25 में 9 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 1 लाख 11 हजार 637 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह रकम गरीबों, किसानों, महिलाओं और जरूरतमंदों तक पहुंची है, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हुई है। डीबीटी की वजह से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और करीब 10 हजार करोड़ रुपये की बचत भी हुई। यह पारदर्शी व्यवस्था योगी सरकार की ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण को दिखाती है।डिजिटल क्रांति ने यूपी को दी नई पहचानयोगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़कर एक नई पहचान बनाई है। यह राज्य अब डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। तकनीक के दम पर यूपी न सिर्फ खुद आगे बढ़ रहा है, बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल भी पेश कर रहा है। डिजिटल लेनदेन और डीबीटी में नंबर वन बनना यूपी के लोगों के लिए गर्व की बात है। सीएम योगी के प्रयासों से राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हर नागरिक के लिए खुशहाली की उम्मीद जगा रहा है।

डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में प्राप्त आपत्ती एवं सुझावों को अंतिम मूल्यांकन दर सूची में समाहित किए जाने हेतु बैठक हुई संपन्न

जिलाधिकारी ने मूल्यांकन दर सूची में समाहित किए जाने हेतु आपत्तिकर्ताओं के सुझाव एवं आपत्तियों का किया अनुश्रवण

साईं मीडिया ब्यूरो
गौतम बुद्ध नगर 07 अप्रैल 2025

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली के तहत गौतम बुद्ध नगर में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण एवं वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन दर सूची में युक्ति-युक्त/तर्कसंगत पुनरीक्षण करके, इसे बाजारी मूल्य के समतुल्य बनाए जाने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं आपत्तिकताओं के साथ बैठक संपन्न हुई।

बैठक में प्रस्तावित मूल्यांकन दर सूची को सभी के समक्ष रखा गया एवं सभी प्रारूपण पर गहन विचार-विमर्श हुआ। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित आपत्तिकताओं की आपत्तियों एवं सुझावों का बहुत ही गहनता के साथ अनुश्रवण करते हुए उनको आश्वस्त किया कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों एवं आपत्तियों पर नियमों के अनुसार विचार-विमर्श करते हुए अंतिम मूल्यांकन दर सूची में समाहित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपत्तिकताओं की आपत्तियों को नियम अनुसार अंतिम मूल्यांकन दर सूची में समाहित करते हुए सूची को और तार्किक बाजार के मूल्य के अनुरूप अंतिम रूप प्रदान किया जाए। उन्होंने स्टांप एवं निबंधन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती जनपद के ग्रामों की कृषि भूमि की दरों का तथा जनपद के भीतर के राजस्व ग्रामों की दरें जो आसपास हो उनको सामान रखने पर भी गहनता से सर्वे करके अंतिम मूल्यांकन दर सूची उसके अनुसार प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह प्रस्तावित मूल्यांकन दर सूची में अंकित वृक्षों की दरों का परीक्षण करते हुए, उनकी सूची उपलब्ध करायें तथा अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि वह प्रस्तावित मूल्यांकन दर सूची के निर्माण की दरों वाले भाग पर अपना मंतव्य समिति को प्रस्तुत करें।

इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, विशेष कार्य अधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण क्रांति शेखर, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव, सहायक आयुक्त स्टांप बुलंदशहर संत कुमार रावत, सहायक आयुक्त स्टांप प्रथम गौतम बुद्ध नगर बीएस वर्मा, सहायक आयुक्त स्टांप ड्यूटी गौतम बुद्ध नगर ब्रिजेश कुमार, तहसीलदारगण, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दादरी, उप निबंधकगण, अन्य संबंधित अधिकारीगण एवं आपत्तिकर्तागण उपस्थित रहे।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा ग्राम चीती तहसील सदर में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का किया गया स्थलीय निरीक्षण

साईं मीडिया ब्यूरो

गौतम बुद्ध नगर 07 अप्रैल, 2025

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निदेर्शों के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे द्वारा आज तहसील सदर के ग्राम चीती में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। किसान अरूण कुमार के खेत गाटा संख्या 362 में पहुंच कर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने फसल की क्रॉप कटिंग के कार्य का निरीक्षण किया एवं निरीक्षण के दौरान 10 .10 .10 त्रिकोण मीटर के क्षेत्र की गेहूं की फसल को निकलवा कर क्रॉप कटिंग के मानक के अनुसार माप करवायी, जिसमें 15.400 किग्रा0 गेहूं निकला।

इस अवसर पर अपर सांख्यिकी अधिकारी अलका चौहान, लेखपाल ग्राम चीती नेत्रपाल सिंह, राजस्व निरीक्षक उदयवीर सिंह एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।

थाना सेक्टर-113(नोएडा):- वजन में घटतौली/बढ़तौली करके वास्तविक वजन से अधिक दिखाकर कंस्ट्रक्शन साइट से निर्धारित कीमत से अधिक कीमत धोखाधड़ी करके वसूलने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त उपकरण व 03 अवैध शस्त्र बरामद।

जनपद में घटित विभिन्न अग्निकांड की घटनाओं को न्यून एवं उसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारी एक्शन में

नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी आपदा नोएडा ने फायर सर्विस से संबंधित अधिकारियों के साथ सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में स्थित एस०एस० ई पैक फ्री फेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का किया भौतिक सत्यापन

साईं मीडिया ब्यूरो
गौतम बुद्ध नगर 07 अप्रैल 2025

जनपद में घटित विभिन्न आपदाओं को रोकने तथा कम करने के उद्देश्य से डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियमित प्रयास सुनिश्चित किये जा रहे हैं।

इसी कड़ी में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा विवेकानंद मिश्र ने आज फायर सर्विस और कारखाना और आपदा विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ सूरजपुर ग्रेटर नोएडा स्थित एस०एस० ई पैक फ्री फेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी में पहुंचकर फायर सुरक्षा की दृष्टिगत भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान जो कमियां पाई गई है, उनको जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाते हुए नोटिस जारी कर फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा सही कराया जाएगा ।

जिलाधिकारी महोदय मनीष कुमार वर्मा द्वारा जनपद में अग्निकांड की घटनाओं को न्यून करने एवं उसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से नगर मजिस्ट्रेट नोएडा विवेकानंद मिश्र के अध्यक्षता और मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे के सह अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। कारखानों का भौतिक सत्यापन की जाएगी। मानक के अनुरूप नहीं पाई जाने पर दी जाएगी नोटिस और होगी अग्निशमन विभाग/कारखाना विभाग और आपदा विभाग के तहत होगी कार्यवाही

थाना फेस-1(नोएडा):- मोबाइल फोन लूटने/चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से लूट/चोरी के 04 मोबाइल फोन, अवैध शस्त्र व घटना मे प्रयुक्त स्कूटी बरामद।

डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कर करेत्तर एवं राजकीय देयों की वसूली के संबंध में समीक्षा बैठक हुई संपन्न

जिलाधिकारी ने रेरा सहित अन्य मदों में अभियान चलाकर वसूली की कार्रवाई तेज करने के दिए निर्देश

गौतम बुद्ध नगर 07 अप्रैल, 2025
साईं मीडिया ब्यूरो

उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राजस्व वसूली को लेकर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजकीय देयों की वसूली की समीक्षा बैठक संपन्न हुयी।

जिला अधिकारी ने स्टांप शुल्क, वाणिज्य कर, आबकारी विभाग, विद्युत विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य समस्त विभागों की समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि शासन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी के सापेक्ष अपनी कार्य योजना तैयार करते हुये राजस्व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीएसटी वसूली में वृद्धि करना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उनके द्वारा अधिक से अधिक एनफोर्समेंट कार्य किए जाएं ताकि अधिक से अधिक राजस्व वसूली सुनिश्चित कराते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। उन्होंने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभागों के द्वारा अपनी कार्य योजना तैयार करते हुए इस प्रकार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए की शासन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसी के अनुरूप राजस्व वसूली करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में रेरा देय की लंबित 2040 आरसी के 554.93 करोड रुपए एवं अन्य मदों की आरसी की तीनों तहसीलों में वृहद अभियान चलाकर वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही कहा कि प्रत्येक सप्ताह तहसीलों में अमीनो के कार्यों की भी समीक्षा की जाए।

इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा व उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव तथा अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

योगी सरकार का मिला सहारा, गरीबी को पीछे छोड़ लखपति बनी सोनभद्र की विनीता

- कौड़ियों के भाव दूध बेचकर गुजारा कर रही विनीता को मिला काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का साथ
- विनीता ने ॐ महिला सहायता समूह के जरिए काशी मिल्क से हाथ मिलाया और अपनी मेहनत को दी नई दिशा
- काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की पहली पांच लखपति दीदियों में से एक हैं विनीता
- सीएम योगी ने हम महिलाओं के सपनों के हकीकत में बदलने का दिया मौका- विनीता
- ग्रामीण आजीविका मिशन की बदौलत हम महिलाएं भी अब अपना परिवार चलाने में सक्षम हैं- विनीता

सांई मीडिया ब्यूरो

लखनऊ/सोनभद्र, 7 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के छोटे से गांव प्रसिद्धी में एक साधारण महिला की असाधारण सफलता आज हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई है, जो अपने सपनों को सच करने की कोशिश में है। एक संयुक्त परिवार की सदस्य विनीता कभी गरीबी और निराशा के साये में जी रही थीं, अब 40 से अधिक गायों की मालिक हैं और काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत आज ह्यलखपति दीदीह्ल बन चुकी हैं। यह सफलता की गाथा केवल उनकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (वढरफ्छट) की क्रांतिकारी पहल का जीवंत उदाहरण है। विनीता की कहानी उन लाखों ग्रामीण महिलाओं के लिए एक मिसाल है, जो योगी सरकार की योजनाओं आर्थिक सशक्तीकरण के रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दे रही हैं।

विनीता की जिंदगी कभी आसान नहीं थी। तरावा ग्राम पंचायत के प्रसिद्धी गांव में रहने वाली यह स्नातक महिला अपने 14 सदस्यों वाले परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालती थीं। विनीता बताती हैं कि उनके पास 10-12 गायें थीं, जिनका दूध वे निजी डेयरियों को बेचती थीं। दिन-रात मेहनत के बावजूद उचित मूल्य और समय पर भुगतान न मिलने से उनका जीवन संघर्षों से भरा था। विनीता याद करते हुए बताती हैं कि पहले हमारी मेहनत का सही फल नहीं मिलता था। दूध बेचने के बाद भी घर का खर्च चलाना मुश्किल था। बच्चों की पढ़ाई और परिवार की बुनियादी जरूरतें एक सपने जैसी थीं। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक नया मोड़ तब लिया, जब उन्होंने काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में सुना। कंपनी की उचित मूल्य नीति और किसानों को हर संभव मदद देने का वादा उनके लिए आशा की एक किरण बन गया। आज उनके पास 40 गाएं हैं, महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है जिसके जरिए वो आज क्षेत्र की तमाम ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई।

विनीता ने ॐ महिला सहायता समूह के जरिए काशी मिल्क से हाथ मिलाया और अपनी मेहनत को नई दिशा दी। कंपनी की मदद से उन्हें उचित मूल्य, प्रशिक्षण और संसाधन मिले। पहले कौड़ियों के भाव बिकने वाला उनका दूध अब उन्हें सम्मानजनक आय देता है। मात्र दो साल में उनकी आय 1 लाख रुपये से अधिक हो गई, और आज उनके पास 40 से अधिक गायें हैं, जिनकी देखभाल वे अपने परिवार के साथ करती हैं। विनीता बड़े गर्व से कहती हैं कि योगी सरकार की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने मेरी जिंदगी बदल दी। काशी मिल्क से समय पर भुगतान और सहायता ने मुझे आत्मविश्वास दिया। अब मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हूं और परिवार को बेहतर जीवन दे रही हूं।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन को नई दिशा दी है। विनीता इस कंपनी की पहली पांच लखपति दीदियों में शामिल हैं। यह बलिया, मिजार्पुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदासनगर जैसे जनपदों में फैली है। इस कंपनी के तहत 700 गांवों की 30,497 महिलाएं जुड़ी हैं, जो प्रतिदिन 1.03 लाख लीटर दूध संग्रह करती हैं। इनमें से 5,209 महिलाएं अब ह्यलखपति दीदीह्ल बन चुकी हैं, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये से अधिक है। बता दें कि प्रदेश भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3,926 गांवों से हर दिन 7.29 लाख लीटर दूध का संग्रह हो रहा है, जिससे 28,853 महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं। बलिनी, सामर्थ्य, गोरखनाथ कृपा और सृजनी जैसी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों ने मिलकर 1,250 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मिशन निदेशक दीपा रंजन ने बताया कि यह पहल केवल महिलाओं को आर्थिक मजबूती नहीं दे रही, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। काशी मिल्क जैसी कंपनियां महिलाओं को सही मंच और संसाधन प्रदान कर रही हैं, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। कंपनी की नीति, जिसमें दूध का भुगतान समय पर सीधे बैंक खाते में होता है, ने महिलाओं को भविष्य के लिए पूंजी जमा करने का अवसर भी दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। योगी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों के जरिए महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन का मंच प्रदान किया है। विनीता की सफलता ने न केवल उनके परिवार को सशक्त किया, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। सही नीति, समर्थन और मेहनत के साथ हर महिला अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती है। योगी सरकार का यह प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ महिलाओं को समाज में नई पहचान दे रहा है।

योगी सरकार के प्रयासों से विनीता की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि उचित बाजार और सहायक बुनियादी ढांचे तक पहुंच ग्रामीण समुदायों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। उनका अटूट दृढ़ संकल्प और काशी मिल्क के समर्थन ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि एक उद्यमी के रूप में उभरने का मौका भी दिया। विनीता कहती हैं कि काशी मिल्क और स्वयं सहायता समूह ने मुझे न केवल आर्थिक मजबूती दी, बल्कि जीने का नया नजरिया भी सिखाया। विनीता की सफलता केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्रांति का प्रतीक है। योगी सरकार की इस पहल ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में एक सकारात्मक बदलाव लाया है।

योगी सरकार की टेली-मानस परामर्श सेवा बनी मानसिक स्वास्थ्य का नया सहारा, जरूरतमंदों को 24 घंटे मिल रही विशेषज्ञ की सलाह

- प्रदेश भर में 64 प्रशिक्षित सलाहकारों द्वारा दूर-दराज आंचल में पहुंच रही परामर्श सेवा
- अक्टूबर-22 में प्रारंभ हुई थी सेवा, अब तक 3 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है लाभ
- औसतन रोजाना 525 कॉलर को सुविधा दे रहे प्रशिक्षित सलाहकार
- केंद्र सरकार ने बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश टेली मानस सेवा को किया है पुरस्कृत

सांई मीडिया ब्यूरो

लखनऊ, 7 अप्रैलः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदृष्टि और संवेदनशील नेतृत्व ने प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दिशा दी है। चाहे वह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य पहचान पत्र का वितरण हो या फिर टेली मेडिसिन के जरिए ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। योगी सरकार हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को आधुनिक और व्यापक बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी क्रम में योगी सरकार की टेली-मानस परामर्श सेवा भी प्रदेशवासियों के लिए भरोसेमंद और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवा के रूप में उभर कर सामने आई है। योगी सरकार मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है। इस कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं पहुंचायी जा रही हैं। इसी के तहत योगी सरकार ने अक्टूबर-22 में टेली मानस परामर्श सेवा शुरू की थी। अब तक इस सेवा का लाभ 3.45 लाख से अधिक लोग उठा चुके हैं।

एनएचएम की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानसिक स्वास्थ्य को आज के दौर की सबसे अहम चुनौतियों में से एक मानते हैं। उनका मानना है कि इससे निपटने के लिए समय पर परामर्श और सहायता बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ टेली-मानस सेवा को शुरू किया गया। वर्तमान में सेवा को प्रदेश के दूरदराज इलाकों तक विस्तार देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिशन निदेशक ने बताया कि सेवा की सबसे बड़ी खासियत इसकी 24 घंटे उपलब्धता है, जिसके माध्यम से प्रदेश भर में मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोग प्रशिक्षित सलाहकारों से निःशुल्क और गोपनीय सलाह ले रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश भर में 64 प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता कार्यरत हैं, जो प्रतिदिन औसतन 525 कॉलर को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

प्रदेश में 4 टेली मानस केंद्र सक्रिय हैं। इनमें मनोरोग विभाग बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल आगरा, मानसिक अस्पताल बरेली और मानसिक अस्पताल वाराणसी शामिल हैं। इन संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञों के माध्यम से कॉलर को प्राथमिक परामर्श, समाधान और जरूरत पड़ने पर आगे की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश टेली मानस सेवा को बड़े राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्रदान किया है। यह पुरस्कार योगी सरकार की सबसे अधिक टेली-मानस कॉल्स का प्रबंधन करने और सेवा की कुशलता को दशार्ता है।

मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने बताया कि 2024-25 में सलाहकारों को 2,13,779 कॉल प्राप्त हो चुके हैं, जबकि सेवा के शुरू होने से लेकर अब तक सलाहकारों को 3,45,783 कॉल प्राप्त हो चुकी है। हर दिन औसतन 525 लोग सेवा का लाभ ले रहे हैं। योगी सरकार ने सेवा की पहुंच को और अधिक सुलभ बनाने के लिए दो हेल्पलाइन नंबर क्रमशः 14416 और 18008914416 (टोल फ्री) जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर विशेषज्ञों से सलाह प्राप्त कर सकता है। यह पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है, जिससे कॉलर को मानसिक रूप से सुरक्षित और सहज अनुभव होता है। मालूम हो कि योगी सरकार की टेली-मानस परामर्श सेवा न केवल मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ा रही है बल्कि मानसिक रोगियों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण परामर्श भी प्रदान कर रही है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सेवा को और विस्तार देने पर विचार कर रहे हैं, ताकि लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सके।

दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर कानपुर समेत 8 पड़ोसी जिलों का होगा विकास

- सीएम योगी के विजन को मिशन मानकर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने शुरू की तैयारी, जीआईएस आधारित ह्यमास्टर प्लान-2051 के जरिए होगा कायाकल्प

सांई मीडिया ब्यूरो

लखनऊ, 7 अप्रैल। उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशल इकॉनमिक जोन (एसईजेड) की प्रक्रिया आगे औद्योगिक विकास के साथ ही इस क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने वाला कदम साबित होगा।

केवल कानपुर ही नहीं, पड़ोसी जिलों को भी मिलेगा लाभ

कानपुर की पहचान न केवल प्रदेश जल्द शुरू होने वाली है। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा इस कार्य को पूरा किए जाना है जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं।

कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी (क्रीडा) के क्रियान्वयन के लिए

- बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, औरैया, कन्नौज तथा कानपुर नगर व देहात के समेकित विकास पर योगी सरकार का जोर
- कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी (क्रीडा) के निर्धारण के जरिए कुल 20,094 वर्ग किमी क्षेत्र में विकासपरक योजनाओं को दी जाएगी गति
- प्रक्रिया के जरिए औद्योगिक विकास के साथ ही ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत खाका तैयार करने पर फोकस

बढ़ा रही है। ऐसे में, कानपुर तथा 8 पड़ोसी जिलों के क्षेत्रों में दिल्ली-एनसीआर के तर्ज पर विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। सीएम योगी का विजन है कि प्रदेश के सबसे पुराने औद्योगिक शहर कानपुर समेत उसके पड़ोसी जिलों को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से विकसित किया जाए। ऐसे में, सीएम योगी के विजन को मिशन मानकर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने जीआईएस आधारित मास्टर प्लान-2051 के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रक्रिया के अंतर्गत बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, औरैया, कन्नौज तथा कानपुर नगर व देहात के अंतर्गत कुल 20,094 किमी वर्ग क्षेत्र में विकासपरक योजनाओं को गति देने के लिए कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी (क्रीडा) के निर्धारण के कार्य को पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। यह बल्कि देश के पुराने व प्रतिष्ठित औद्योगिक शहरों में शामिल नगर की रही है। इसके बावजूद, कानपुर व उसके आसपास के जिलों में असंतुलित शहरी विकास की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित व सामंजस्यपूर्ण शहरीकरण को बढ़ावा देने के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।

इसी कड़ी में, कानपुर क्षेत्र के परिसीमन के साथ ही आठ जिलों को शामिल करके दिल्ली-एनसीआर के तर्ज पर कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी (क्रीडा) के निर्धारण के कार्य को पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित मास्टर प्लान-2051 के निर्माण की प्रक्रिया एक क्षेत्रीय योजना तैयार करने पर फोकस है जो क्षेत्र में भूमि उपयोग के नियंत्रण तथा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियों का प्रावधान करने में मददगार होगी। इस कार्य को पूरा करने का माध्यम मास्टर प्लान-2051 बनेगा। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होगी जो क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी के लिए तंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह कानपुर के उपनगरीय क्षेत्रों के आसपास अव्यवस्थित विकास को नियंत्रित करने के साथ उद्यमियों को संगठित निवेश के अवसर प्रदान करेगा।

इससे नगर विकास, औद्योगिक क्षेत्रों तथा आवासीय-अनावासीय संरचनाओं के निर्माण समेत भविष्य की जरूरतों के अनुसार सभी संसाधनों के विकास, संचालन व प्रबंधन की प्रक्रिया को बल मिलेगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट टीम की तैनाती होगी जिसकी प्रक्रिया जारी है।

मिशन रोजगार: 1000 अप्रेन्टिसशिप और कामगार पदों के लिए कैम्पस ड्राइव

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में 9 अप्रैल को टाटा मोटर्स लिमिटेड का कैम्पस ड्राइव

- कैम्पस ड्राइव में महिला एवं पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं
- आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों को हाईस्कूल और विभिन्न आईटीआई ट्रेडों में योग्यता आवश्यक
- अस्थायी कामगार पदों के लिए एक वर्ष का अनुभव भी जरूरी
- चयनित अप्रेन्टिस को ₹13,060 और अस्थायी कामगारों को ₹14,827 मासिक वेतन के साथ अन्य सुविधाएँ भी

सांई मीडिया ब्यूरो

07 अप्रैल, लखनऊ। योगी सरकार विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों की मदद से युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में 09 अप्रैल को टाटा मोटर्स लिमिटेड, लखनऊ द्वारा एक दिवसीय कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अप्रेन्टिसशिप एवं अस्थाई कामगार पदों पर कुल 1000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यह कैम्पस ड्राइव दिन बुधवार को प्रातः 10:00 बजे से संस्थान परिसर में प्रारंभ होगा।

आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए सुनहरा मौका संस्थान के प्रधानाचार्य राज कुमार यादव ने बताया कि इस रोजगार मेले में महिला एवं पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह अवसर आई.टी.आई. उत्तीर्ण युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, जिसमें सीधे उद्योग से जुड़ने और अपना भविष्य सुरक्षित करने का अवसर प्राप्त होगा। संस्थान के ट्रेनिंग, काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर एम. ए. खाँ ने बताया कि टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा अप्रेन्टिसशिप के साथ-साथ अस्थाई कामगार के रूप में कार्य करने के लिए चयन किया जाएगा। अप्रेन्टिसशिप हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल के साथ इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, पेंटर जनरल, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल इंजन, ऑटोमोटिव सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन, सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, टेक्नीशियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिक (सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग), इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस (क्छळरट), इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस लीड टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट, मैकेनिक (डोमेस्टिक, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीन), मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक मैक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव मैक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स (इनवर्टर, यूपीएस और ड्राइव्स की मेंटेनेंस), वायरमैन कंट्रोल पैनल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उडढअ (कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट) व्यवसायों में आई.टी.आई. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अस्थाई कामगार पद हेतु चयन में उन्हीं व्यवसायों के साथ हाईस्कूल एवं आई.टी.आई. के साथ कम से कम 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अप्रेन्टिसशिप के अंतर्गत ₹13,060 मासिक स्टाइपेन्ड तथा अस्थाई कामगार के रूप में ₹14,827 मासिक वेतन प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। समस्त डॉक्यूमेंट्स के साथ हों उपस्थित सभी इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे 09 अप्रैल 2025 को प्रातः 10:00 बजे अपने विस्तृत बायोडाटा, समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं छायाप्रति सहित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ के परिसर में समय से उपस्थित होकर इस रोजगार अवसर का लाभ उठाएं।

अभ्युदय पोर्टल और एआई के माध्यम से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को बनाया जा रहा है प्रभावी

- अभ्युदय पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुकी है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और प्रशासकीय अधिकारी जुड़ेगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से
- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को पहुंचाया जाएगा ब्लाक स्तर तक
- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से वर्ष 2024-25 में लाभान्वित हुए हैं प्रदेश के 23,017 गरीब छात्र

सांई मीडिया ब्यूरो

07 अप्रैल झ लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से वर्ष 2021 से प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत दी जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निदेशों के अनुरूप समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से अब तक 82 हजार से अधिक छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। एक ओर अभ्युदय पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम को गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए एआई और प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को मॉक इंटरव्यू और प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही योजना को ब्लाक स्तर पर संचालित करने का प्रयास भी चल रहा है।

सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को और अधिक प्रभावी बनाने और इसकी पहुंच ग्रामीण परिवेश के छात्रों तक पहुंचाने के लिए अभ्युदय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अभ्युदय पोर्टल के माध्यम से एक ओर छात्र प्रदेश के कोने-कोने से सुविधाजनक तरीके से आवेदन कर सकेंगे। सत्र में सबसे पहले यूपीएसी और यूपीपीसीएस की परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू हो गये हैं। साथ ही शिक्षक भी एआई और पोर्टल के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस सत्र से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ताकि ग्रामीण परिवेश के जरूतमंद छात्र अपने घरों के समीप ही आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। वर्तमान में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 166 प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी संख्या सत्र में बढ़ाये जाने की योजना है।

परीक्षा - सफल हुए छात्र

यूपीएसी - 46

यूपीपीसीएस- 121

एनईईटी - 86

जेईई - 35

अन्य भर्ती परीक्षा - 455 से अधिक

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को अभ्युदय योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी समय-समय पर प्रशासकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ छात्रों को प्रशिक्षण और मॉक इंटरव्यू में मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इस प्रक्रिया को इस सत्र से योजनाबद्ध ढ़ग से चालाया जाएगा। वर्तमान में 500 से अधिक आईएएस, 450 आईपीएस और लगभग 300 आईएफएस अधिकारी अभ्युदय पोर्टल के माध्यम से वर्चुअल और रियल गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं।साथ ही कई अन्य विषयों के विशेषज्ञ भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं । यूपीएससी व पीसीएस की सक्षात्कार परीक्षा के लिए अब तक 10 मॉक इंटरव्यू का संचालन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत अब तक प्रदेश के 743 से अधिक छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं।

सम्पादकीय

संघ-भाजपा में तालमेल

भले ही प्रसंग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सौ साल पूरा होने का हो, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की संघ के मुख्यालय की पहली यात्रा के गहरे निहितार्थ भी हैं। जो इस बात का संकेत है कि पिछले आम चुनाव के दौरान संघ व भाजपा के रिश्तों में जिस खटास की बात कही जा रही थी, वह संवाद व संपर्क से दूर कर ली गई है। जो इस बात का भी संकेत है कि आने वाले वक्त में पार्टी व सरकार के अहम फैसलों में संघ की भूमिका बढ़ सकती है। यूं तो प्रधानमंत्री ने बीते रविवार को नागपुर यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी की, लेकिन उनका प्रधानमंत्री के रूप में संघ मुख्यालय पहुंचना खास चर्चा में रहा। उल्लेखनीय है कि चौथाई सदी पहले संघ मुख्यालय पहुंचने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। साथ ही वे संघ की रीति-नीतियों से भली-भांति परिचित हैं। लेकिन पिछले आम चुनाव के दौरान भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऐसे बयान चचाओं में थे कि पार्टी का कद संघ से बड़ा हो गया है। जिसके चलते संघ व भाजपा के रिश्तों में कुछ कसक देखी गई। जिसकी कुछ इस तरह व्याख्या की गई कि पार्टी जिस तरह चार सौ पार के लक्ष्य से चूकी, उसके मूल में संघ कार्यकताओं की उदासीनता रही है। बाद में दोनों के रिश्ते सामान्य होने के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो आशातीत सफलता हाथ लगी, कहा जा रहा था कि उसमें संघ कार्यकताओं का समर्पण व योगदान महत्वपूर्ण घटक रहा। अब संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री की यात्रा से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि दोनों की रीतियों-नीतियों फिर से बेहतर तालमेल स्थापित हुआ है। अब राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के फैसलों में संघ के दृष्टिकोण का प्रभाव नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में संघ की भूमिका हो सकती है। ऐसा ही असर बदलते वक्त के साथ पार्टी के अन्य फैसलों पर भी नजर आ सकता है। यानी दोनों अब सामंजस्य व सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे। अर्थात पार्टी अब अपने वैचारिक स्रोत के साथ बेहतर तालमेल करके चलना चाहेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने संघ मुख्यालय में कहा कि संघ का विचार बीज अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने संघ कार्यकताओं के योगदान की चर्चा करते हुए संघ को भारतीय संस्कृति का विशाल वट वृक्ष बताया। बहरहाल, भाजपा संघ से कुछ मुद्दों पर असहमति से आगे निकल चुकी है। उल्लेखनीय है कि आम चुनाव परिणाम के बाद संघ प्रमुख ने नसीहत दी थी कि लोगों की सेवा करने वाले एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी कतिपय उन नेताओं की तरफ इशारा भी था जिन्होंने कहा था कि पार्टी बड़ी हो गई है और उसे संघ की पहले की तरह जरूरत नहीं है। इसके बाद संघ ने अपने महत्व का अहसास पार्टी को कराया। जिसका राजनीतिक लाभ भाजपा को कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिला भी। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नागपुर यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों का निष्कर्ष यह भी है कि संघ परिवार की अब सरकार व पार्टी में भूमिका बढ़ सकती है। राजनीतिक पंडितों को तब आश्चर्य नहीं होगा यदि पार्टी के नये अध्यक्ष के चयन में संघ की मोहर लगे। यह भी हकीकत है कि लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते पूर्ण बहुमत से दूर रहने के कारण पार्टी की सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ी है। जिसके चलते भाजपा अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिये संघ पर अधिक निर्भर रहेगी। निर्विवाद रूप से आने वाले समय में पार्टी को पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। ऐसे में भगवा पार्टी को अगले दो वर्षों में बड़ी सफलता हासिल करने के लिये संघ पर निर्भर रहना पड़ेगा। जहां संघ अपनी आधार भूमि को विस्तार दे रहा है।

वक़्फ़ (संशोधन) बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली- नया कानून अस्तित्व में आया- यूनिफाइड मैनेजमेंट एंपावरमेंट इंपिरिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) नाम हुआ

वक़्फ़ के नए कानून उम्मीद को पाँच विपक्षी पार्टियों ने अलग- अलग याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर हर लोकतांत्रिक देश में भारतीय भाषा में कहे तो वहां की संसद के दोनों सदनों में लोकतांत्रिक तरीके से ही कोई भी बिल पास करके उसे कानून का दर्जा देकर क्रियान्वयन किया जाता है,उसी कड़ी में भारत में एक और अध्याय वक़्फ़ संशोधन बिल 2025 के रूप में जुड़ गया है,जो दोनों सदनों में पारित होकर दिनांक 5 अप्रैल 2025 को देर शाम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब 'उम्मीद' नाम से कानून बन चुका है व आम जनता की जानकारी के लिए इसे गजट में भी प्रकाशित कर दिया गया है, अब इस कानून को कब से लागू करने की अधिसूचना जारी की जाती है इसपर सभी की नजरें लगी हुई है, चूँकि वक़्फ़ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है,नया कानून अस्तित्व में आया गया है अब उसका नाम यूनिफाइड मैनेजमेंट एंपावरमेंट इंपिरिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) हुआ इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर वक़्फ़ के बदले नए कानून उम्मीद को लागू करनेकी तारीख बताएगी व नियम भी बनाए जाएंगे।

साथियों बात अगर हम वक़्फ़ संशोधन बिल 2025 के कानून बन जाने की करें तो,वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब कानून भी बन गया है,इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था।राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया, जो कि पूरे देश में लागू होगा।संसद के उच्च सदन राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे, इससे पहले लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे।दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया था।विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से बिल वापस लेने की अपील भी की थी। इस बिल को लेकर सरकार का दावा है कि इससे वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। गरीब मुसलमान जो अपने अधिकारों से वंचित रहते थे, उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे, देश में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार की दिशा में एक अहम कदम है।संशोधन और राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद अब इस बिल का नाम यूनिफाइडमैनेजमेंट एपावरमेंट इफ़िफ़इंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) हो गया

है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को वक्फ संपत्तियों पर समान उत्तराधिकार अधिकार मिले, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों का महत्वपूर्ण व अहम हिस्सा है।

साथियों बात अगर हम इस कानून के प्रावधानों की करें तो, (1) वक्फ बोर्ड की संरचनाः बोर्ड में इस्लाम के सभी फिकरों को प्रतिनिधित्व मिलेगा. केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे, जिनमें चार गैर-मुस्लिम से अधिक नहीं होंगे। (2) वक्फ संपत्ति पर नियंत्रणः वक्फ बोर्ड की देखरेख के लिए परमार्थ आयुक्त (चैरिटी कमिश्नर) की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्तियों का उचित मैनेजमेंट हो रहा है। (3) विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के अधिकारों की रक्षाः कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है लेकिन विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ बच्चों के अधिकार वाली संपत्तियों को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। (4) विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनलः देशभर में वक्फ से जुड़े 31,000 से अधिक मामले लंबित हैं, इसलिए वक्फ न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त बनाया गया है. साथ ही अपील का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिससे असंतुष्ट पक्ष दीवानी अदालत में जा सकता है। (5) राष्ट्रीय संपत्ति और स्मारकों की सुरक्षाःभारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाली संपत्तियों को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा।क्यों लाया गया विधेयक ? संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा था, 2006 में देश में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, जिनसे मात्र 163 करोड़ रुपये की आय हुई। 2013 के संशोधन के बाद भी यह आय केवल तीन करोड़ रुपये बढ़ी। वर्तमान में देश में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं लेकिन इनके प्रबंधन को प्रभावी बनाने की आवश्यकता थी।

साथियों बात अगर हम इस कानून में जिला कलेक्टर की अहम भूमिका की करें तो, कलेक्टर की भूमिका होगी अहम एक प्रमुख प्रिंट मीडिया पेपर में में छपी एक रिपोर्ट में अधिवक्ता विशेषज्ञ ने कहा कि विधेयक में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें लागू करना आसान होगा। जैसे कि मूल

अधिनियम के तहत निरस्त किए गए सेक्शन। वक्फ संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार पहले वक्फ बोर्ड के पास था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इसे तुरंत लागू किया जाएगा। कुछ प्रावधानों को लागू करने में समय लगेगा। खासकर कलेक्टर द्वारा की जाने वाली जांच की प्रक्रिया को स्पष्ट करने में। जब वक्फ बोर्ड किसी मामले को कलेक्टर को भेजता है, तो जांच कैसे होगी, इसके नियम बनाए जाएंगे। कुछ संशोधनों के लिए केवल प्रक्रियात्मक बदलावों की आवश्यकता होगी।उनके अनुसार सरकारी संपत्तियों और नामित अधिकारियों की भूमिका से संबंधित प्रावधानों को भी नियमों में स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, सरकारी संपत्तियों के लिए,एक नामित अधिकारी होगा। यह अधिकारी कौन होगा, उसका कार्यकाल और अधिकार क्षेत्र क्या होगा, यह नियमों में बताया जाएगा।नियमों को प्रकाशित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इन नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर प्रिंट मीडिया में बताया कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद नियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि नियमों को प्रकाशित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मंत्रालय विधेयक और संशोधनों को लेकर स्पष्ट है। एक बार नियम बन जाने के बाद, उन्हें कानून बनने के छह महीने के भीतर प्रकाशित करना होगा। कुछ मामलों में, समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। कुछ नियमों के लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसमें फीडबैक के लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया के दौरान कई सुझाव आते हैं, तो प्रकाशन की समय सीमा छह महीने तक बढ़ सकती है। जिन नियमों के लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए समय सीमा विधेयक के अधिनियमित होने से छह महीने है। लोकसभा के पूर्व महासचिव से बात करते हुए विधेयक के अगले कदमों के बारे में बताया।उन्होंने कहा कि एक बार राष्ट्रपति की सहमति मिलने और इसे गजट में अधिसूचित किए जाने के बाद, संशोधित विधेयक में कुछ प्रावधान हो सकते हैं जो नियमों के लिए हैं और कुछ संशोधन पहले से ही वर्णित हैं। विधेयक का खंड 41 एक नया सेक्शन जो केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देता है। किसी अधिनियम को तभी लागू किया जा सकता है जब नियम बनाए और अधिसूचित किए जाएं, इसलिए नियमों को तत्काल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ मामलों में, सरकार विधेयक को संसद में पेश किए जाने या पारित होने से पहले ही नियम बना लेती है, ताकि जैसे ही यह पारित हो, नियमों को अधिसूचित शीघ्र ही सरलता से किया जा सके।

साथियों बात अगर हम कानूनी विशेषज्ञ की राय की करें तो, सुप्रीम कोर्ट के एक विशेषज्ञ अधिवक्ता ने कहा कि संशोधन वक्फ के रूप में संपत्ति घोषित करने वालों को प्रतिबंधित करता है। इसे केवल उन मुसलमानों तक सीमित करता है जो कम से कम पांच वर्षों से मुसलमान हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे निर्धारित किया जाएगा। बिल में वक्फ बोर्ड द्वारा भेजे गए मामलों में कलेक्टर द्वारा जांच करने की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के सामने विधेयक पर एक प्रस्तुति भी दी थी। विधेयक में कुछ प्रावधानों को लागू करना आसान होगा, जबकि कुछ के लिए नियमों को बनाने में अधिक समय लगेगा। वहीं सरकार को उम्मीद है कि नियमों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल, 2025 को इसकी स्वीकृति दे दी है। अब यह कानून बन चुका है और आम लोगों की जानकारी के लिए इसे प्रकाशित किया गया है। यह जानकारी पीटीआई की रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है। सरकार ने कहा है कि नए कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना, गड़बड़ी रोकना और अवैध कब्जों पर लगाम लगाना है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि वक़्फ़ (संशोधन) बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली- नया कानून अस्तित्व में आया- यूनिफाइड मैनेजमेंट एंपावरमेंट इंपिरिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) नाम हु।वक़्फ़ के नए कानून उम्मीद को तीन विपक्षी पार्टियों ने अलग-अलग याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मुसलमान वक़्फ़ अधिनियम 1923 को भारतीय गजट में अधिसूचना जारी कर निरस्त किया गया।केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर वक़्फ़ के बदले लाए गए कानून उम्मीद को लागू करने की तारीख बताई जाएगी व नियम बनाए जाएंगे

महाराष्ट्र में फिर सक्रिय हो रहे हैं राज ठाकरे

(डॉ.मुकेश 'कबीर'- विनायक फीचर्स)

गुड़ी पड़वा पर राज ठाकरे की विशाल सभा और उनके भाषण की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रही है,उनकी सभा को बहुत सफल बताया जा रहा है और इसकी तुलना बाला साहेब की सभाओं से हो रही है क्योंकि राज ठाकरे की इस सभा में लोगों की संख्या इतनी थी कि पूरा शिवाजी पार्क फुल था,ऐसा सिर्फ बाला साहेब की सभाओं में होता था। आमतौर पर राज ठाकरे की सभाओं को सत्ता पक्ष भी एक लेसन लर्निंग भाषण की तरह लेता है क्योंकि राज ठाकरे हमेशा ऐसा कुछ न कुछ जरूर बोलते हैं जिसे सुनकर महाराष्ट्र सरकार अपने निर्णय में सुधार करती है। मुंबई में आम धारणा है कि भले ही राज ठाकरे की पार्टी चुनाव में ज्यादा सफल न हो लेकिन राज ठाकरे क्या बोलते हैं इसमें सबको इंट्रेस्ट होता है। यहां तक कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता भी राज की सभाओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले कहते हैं कि 'इस बार की सभा में राज ने सरकार को दिशा देने वाली कोई बात नहीं की लेकिन जनता की भारी संख्या के कारण यह एक सफल सभा मानी जाएगी जो भविष्य में महाराष्ट्र को प्रभावित जरूर करेगी।' असल में राज ठाकरे के समर्थकों का मानना है कि वे जो बोलते हैं उसमें उनकी महाराष्ट्र के प्रति चिंताएं साफ झलकती हैं और महाराष्ट्र को गर्व होना चाहिए कि उनके पास कम से कम एक नेता तो ऐसा है जो राजनीति से ऊपर उठकर महाराष्ट्र और मुंबई के बारे में कुछ सोचता है,बोलता है। आजकल राज जैसे नेता देश में नहीं मिलते हैं जो अपने

प्रांत और अपने लोगों के लिए मुखरता से बात रखते हैं जबकि इस मुखरता का उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। वैसे राज ठाकरे ऐसे नेता हैं जिनमें अपने गुरु की पूरी झलक दिखाई देती है,आमतौर पर ऐसे उत्तराधिकारी कम देखने को मिलते हैं जिनमें अपने गुरु की इतनी गहरी छाप देखने को मिले लेकिन राज पूरी तरह से बाला साहेब नजड़ आते हैं और उन्हीं की तरह ही बात रखते हैं और वैसी ही उनकी राजनीतिक शैली है ,बाला साहेब की ऐसी झलक उद्धव ठाकरे में भी दिखाई नहीं देती और न ही बाला साहेब के स्वघोषित उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे में। राज महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर तो करते हैं लेकिन अब दिक्कत यह है कि देश की राजनीति काफी बदल चुकी है इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है वरना राज ठाकरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के भी सबसे बेहतरीन नेताओं में गिने जा सकते हैं। राज की राजनीतिक समझ का अंदाज तो इस बात से भी लग जाता है कि इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल का जवाब मीडिया और बीजेपी के पास भी नहीं था तब राज ने कह दिया था कि फडणवीस जी अगले मुख्यमंत्री होंगे,खास यह कि उन्होंने यह बात चुनाव से पहले ही कह दी थी और तब उनका इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे लेकिन परिणाम यही आया बीजेपी जीती और फडणवीस मुख्यमंत्री बने जबकि यह निर्णय लेने में बीजेपी को भी बीस दिन से ज्यादा का समय लगा था लेकिन आखिर में राज सही साबित हुए। हालांकि इस बार राज ठाकरे का एक भी कैंडिडेट चुनाव जीतकर नहीं आया लेकिन उसका कारण यह रहा कि इस बार लाडली बहना जैसी मुफ्त की योजनाएं महाराष्ट्र में भी असर कारक रहीं जिसकी उम्मीद मराठी लोगों को भी नहीं थी और राज शुरू से ही इस योजना का खुलकर विरोध कर रहे थे। राज के अनुसार इस तरह की योजनाएं देशहित में नहीं है,संभवतः यही साफगोई राज को भारी पड़ी । राज की दूसरी कमजोरी यह है कि वे वर्तमान राजनीति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। उनके समकालीन जितने भी नेता हैं सभी के सभी जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगे है फिर चाहे अखिलेश यादव हों या ममता बनर्जी या फिर फडणवीस या फिर उद्धव ठाकरे भी लेकिन राज आज भी महाराष्ट्र की बात करते हैं, जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं। राज ठाकरे आज भी एक ऊर्जावान नेता हैं उनको जनसमर्थन भी मिल रहा और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है लेकिन यह वोट बैंक में कब तब्दील होगी यह सवाल जरूरी है। राज की दिक्कत यह है कि अब सत्ता में बीजेपी है जो खुद के अलावा किसी और को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति करने नहीं देती इसलिए बीजेपी ने एक एक करके सारे हिंदूवादी पार्टी और संगठनों को कमजोर कर दिया है और राज को भी इस चुनाव में बीजेपी के कारण नुकसान हुआ है और आगे भी उनकी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी ही रहेगी ,इस चुनौती से कैसे निपटना है यह राज को तय करना होगा। मुझे लगता है सिर्फ मराठी मानुष और मराठी अस्मिता ही राज को फिर से उभार सकते हैं , इसीलिए उनको इस पर ही कायम रहना चाहिए,शायद उन्हें भी इसका अंदेशा जरूर है इसलिए वो मराठी एकता की बात भी करते हैं और मुंबई की भी । अब देखते है राज का जादू कितना प्रभावी होगा,वैसे राज ठाकरे के समर्थकों का तो यही कहना है कि यदि बाला साहेब टाइगर थे तो राज निश्चित रूप से उनका छावा है। (विनायक फीचर्स)

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के तीन वर्षों का सफर

(सुभाष आनंद-विनायक फीचर्स)

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर उसके द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां के जो दावे किए हैं उसके बारे में पूरी गंभीरता से विश्लेषण किए जाने की जरूरत है।

आम आदमी पार्टी ने सरकार में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे ,उसमें कितने पूरे हुए और कितने अधूरे बचे हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने की भी जरूरत है। पंजाब सरकार द्वारा बताई गई उपलब्धियों के संबंध में विरोधी पक्ष अकाली दल और कांग्रेस ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया, यह सरकार नादानों की सरकार है, जिसे सरकार चलाने का कोई ढंग नहीं और सरकारी तंत्र के सुस्त होने की बात कही। ये बात आप को याद होगी कि अकाली भाजपा के 10 वर्ष के शासन काल और बाद में कांग्रेस के 5 वर्ष के शासन काल से तंग आकर लोगों ने बदलाव लाने की ठानी, लोगों को आम आदमी पार्टी से बहुत आशाएं थीं ,लोगों ने आम आदमी पार्टी को इसलिए ही चुना था कि न्याय का राज्य होगा, लोगों की आर्थिक मुश्किल कम होगी, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य मिलेगा, परंतु तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात लोगों को घोर निराशा ही देखने को मिल रही है। पंजाब के विधायक निरंकुश हो चुके हैं, कुछ किसानों की ट्रालियां चोरी कर रहे हैं, कुछ ट्रक यूनियन के प्रधानों के पद बेचते रहे, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं, कुछ गुंडागर्दी में लगे हुए हैं ,आज पंजाब में आम आदमी का अस्तित्व खोता जा रहा है । सरकार की आर्थिक स्थिति तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, कर्ज लेकर कार्य चलाने पड़ रहे हैं, 3 करोड़ 15 लाख का कर्ज इस सूबे के सिर पर चढ़ गया है, जिसका बोझ सहन करना इसके लिए अति मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि सरकार की बड़ी आमदनी इस कर्ज का ब्याज अदा करने में जा रही है। सरकार कर्ज लेकर चल रहीं हैं, कर्ज का बोझ

लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब में बढ़ते नशे को रोकने के लिए पूर्व सरकारों की भांति यह सरकार भी बुरी तरह असफल रही है, 3 वर्ष पूरे होने के पश्चात नशा विरोधी युद्ध में केवल छोटे-मोटे नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है जबकि बड़े-बड़े मगरमच्छ सरकार की पहुंच से बाहर है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक और दो मंजिला मकानों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। जबकि बड़े-बड़े बंगलों और बड़ी कोठियों वालों को राजनीतिक और पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। यहां आज भी युवा लोग नशे से ग्रस्त है, पिछले सप्ताह मात्र 5 दिनों में पंजाब में 15 से ज्यादा मौतें नशे का ओवरडोज लेने से हो गई है, सरकार बड़े-बड़े नशा तस्करों को समाप्त करने में सफल नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी के नेता कहा करते थे कि पंजाब में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा, आज परिवहन के मामले में मुी भर लोगों का हाथ ,माइनिंग के क्षेत्र में रेत बजरी का काला धंधा पहले की तरह चलते रहने और शराब माफिया को और मजबूत होने पर आम आदमी नेताओं की पोल खुल गई है। भगवत सिंह मान ने आने वाले वर्षों में एक लाख सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में 20 लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी,लेकिन 3 वर्षों के शासनकाल में इस क्षेत्र में दर्शाए या निर्धारित लक्ष्य का कहीं अता पता नहीं है। लाखों की बजाय कुछ हजार नौकरियां देकर जनता में वाहवाह प्राप्त करने की कोशिश की गई है। बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप देना आज बहुत दूर की बात रह गई है। महिलाओं को प्रति माह हजार रुपए देने की बात हवा हवाई हो चुकी है। 3 वर्ष बीत जाने के पश्चात चौथे वर्ष के बजट में भी महिलाओं को 1000 रुपए देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जोर-जोर से प्रचार किया था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को पक्का करने और किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की बात की थी,इन सब मामलों में आज वोटर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे है।

होटलों में देह व्यापार, जुए के अड्डे ,गैर कानूनी कामों के ठेके बढ़ रहे हैं। मान सरकार जिसका नारा है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, इसी राज्य में भ्रष्टाचार के रेट बढ़ गए हैं ,नशा बेचने वाले कैमिस्टों से मोटी रकमें वसूली जा रही हैं। (विनायक फीचर्स)

संक्षिप्त समाचार

प्रयागराज में टला बड़ा हादसा : अटरामपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला लोहे का पोल

प्रयागराज, एजेंसी। फाफामऊ-ऊंचाहार रूट पर अटरामपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लोहे का एक पोल मिला। पटरी से एक मालगाड़ी गुजरने वाली थी, लोको पायलट ने पोल को देख लिया तो आपातकालीन ब्रेक लगाकर मालगाड़ी रोक दी।घटना की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दी गई और पोल को पटरी से हटाया गया। पोल किसने रखा अभी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। आरपीएफ, जीआरपी के साथ इंटेलिजेंस को भी सक्रिय किया गया है।मालगाड़ी के लोके पायलट संयोग शर्मा ने बताया कि वह मालगाड़ी को लेकर ऊंचाहार की ओर जा रहे थे। भोर में लगभग सवा चार बजे पटरी पर पोल दिखा था। मामले में ट्रेन मैनेजर प्रवीण ने भी अपनी रिपोर्ट दी है कि पोल से दुर्घटना हो सकती थी और मालगाड़ी पटरी से उतर सकी थी। फिलहाल इसे ट्रेन पलटाने के लिए साजिश माना जा जा रहा है। मामले में प्रयाग के आरपीएफ प्रभारी आरबी सिंह ने बताया कि प्रयाग आरपीएफ पोस्ट में मामले की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। पोल रखने वालों का पता लगाया जा रहा है।

गर्मी से लोगों का हाल-बेहाल! यूपी के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार

लखनऊ, एजेंसी। प्रदेश में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। शनिवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।वहीं, आने वाले दिनों में लखनऊ में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया।शनिवार को कानपुर (आइएएफ) में तापमान 40.3 डिग्री, वाराणसी (बीएचयू) में 40.5 डिग्री और प्रयागराज में सबसे अधिक 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा फतेहपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, हमीरपुर जैसे जिलों में भी पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया।प्रदेश के जिन जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया, उनमें लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, कानपुर नगर, गोरखपुर, बलिया, फतेहपुर, सुल्तानपुर, फुर्सतगंज, फतेहगढ़, बस्ती, झांसी, हमीरपुर, बरेली, नजीबाबाद और मेरठ शामिल हैं। सुल्तानपुर और प्रयागराज सबसे गर्म जिले रहे। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की आशंका है। कुछ क्षेत्रों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह के अनुसार, आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

भू माफिया घोषित करने के लिए नया कानून लाएगी सरकार

लखनऊ, एजेंसी। यूपी सरकार किसी को भू माफिया घोषित करने के लिए जल्द ही नया कानून लेकर आएगी। अभी तक यह फैसला डीएम और एसपी के द्वारा जिले स्तर पर होता है। प्रदेश सरकार भू माफिया घोषित करने के लिए नया कानून लाएगी। सिर्फ शासनादेश के तहत कार्रवाई किए जाने से मामले अदालत में टिक नहीं पा रहे हैं। इसलिए अध्ययन करके नया कानून लाने या पहले से मौजूद कानून में संशोधन का फैसला उच्चस्तर पर लिया गया है। यूपी में भू माफिया चिह्नित करने के लिए एक मई 2017 को शासनादेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व्यक्ति का विश्लेषण कर भू माफिया के तौर पर उसको चिह्नित करेंगे।

बाबा साहेब के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का सपाईयों ने लिया संकल्प

बॉबी राजपूत संवाददाता - समाजवादी पार्टी जिला आगरा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण वर्मा एवं महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार की अध्यक्षता में मासिक बैठक हुई बैठक में कार्यकताओं को पार्टी को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई श्रीकृष्ण वर्मा जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने सयुंक्त रूप कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओ कार्यकताओं और जिला कार्यकारणी के सभी पदाधिकारीयों को दिशा निर्देश दिए की अपने अपने विधानसभा में पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिये अपनी अपनी विधान सभा में अभी से लग जाय जनता के बीच में जाकर ज्यादा से ज्यादा पीडीए की बात करें भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीडीए के विरोध में रही है भारतीय जनता पार्टी में पीडीए अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है

श्रीकृष्ण वर्मा ने कहा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार 27 जनवरी से हर विधानसभा में बूथ

बाइस सेक्टर वाइज पीडीए पंचायत हो रही है पीडीए पंचायत में हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ रहा है और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकताओं को निर्देश दिए की छोटी-छोटी नुक्कड़ सभा में पीडीए पंचायत करें और सपा सरकार में हुए कार्यकाल को बताएं और कार्यकताओं से कहा कि वे सब भाजपा की साजिशों को विफल करने का संकल्प लेकर जायें। बूथ को मजबूत करना है और वोटरलिस्ट पर पूरी नजर रखकर उसे ठीक कराना है। कार्यकर्ता सतर्क रहेंगे तो भाजपा धांधली नहीं कर पाएगी।

इस दौरान ममता टपलू, प्रदेश सचिव नितिन कोहली,प्रवीण राजपूत, तेजवीर बघेल, राहुल चौधरी, सुलेखा श्रीवास्तव,अखिलेश यादव, हरिमोहन लोधी (प्रधान) महानगर महासचिव , राकेश धनकर, पवन प्रजापति जिला मिडिया प्रभारी,प्रदीप सिंह ,शिवपाल यादव ,देवेंद्र राजपूत,सोमेश गुप्ता, सोनेलाल कश्यप,शरीफ मलिक, आदित्य गौतम,खेमबाबू,राकेश गोला, सोनेलाल कश्यप,असलम वारसी,आदि लोग मौजूद रहे

मुसलमानों के बाद भाजपा की नजर कैथोलिक ईसाइयों की जमीन पर, संजय सिंह का बड़ा बयान

मेरठ, एजेंसी। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि वक्फ के बाद अब भाजपा की नजर कैथोलिक ईसाइयों की भूमि पर है। वह एजुकेशन ऐंड बुनकर विकास समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बुढ़ाना गेट स्थित अपार चेम्बर में आये थे।

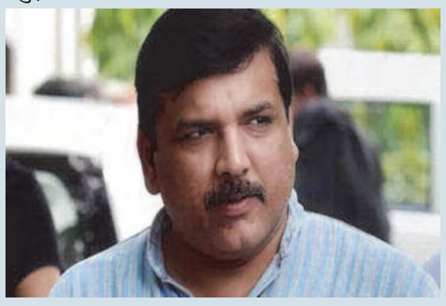

पत्रकारों से बात करते हुए आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि कैथोलिक ईसाइयों के पास वक्फ से कहीं ज्यादा भूमि है। इसके बाद सिख, बौद्ध और जैन धर्म की जमीनों को लेकर भी वक्फ संशोधन विधेयक जैसा बिल लाया जायेगा।

कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान द्वारा दिये गये मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार में बैठे गुजरात के दो लोग देश की संपत्ति बेच रहे है, गुजरात के दो पूंजीपति अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कह रहे हैं कि गोबर से युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। तंज भरे लहजे में उन्होंने कहा कि प्रदेश का पढ़ा-लिखा युवा गोबर से रोजगार करेगा। दिल्ली में अब बुजुर्गों को पार्क में जाने के लिए 50-50 रुपए शुल्क देना पड़ रहा है और स्कूलों की फीस बढ़ रही है। आप लोगों को आप पार्टी की याद आ रही है।

वक्फ के रूप में संपत्तियों को दर्ज करने के बाद बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े का चिट्ठा जल्द ही सामने लाया जाएगा। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज ऐसी 83 हजार गुम संपत्तियों का पता लगाया जाएगा, जिनको पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी पर फायरिंग, मां-बेटे बाल-बाल बचे

बेलघाट, एजेंसी। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की रात थार गाड़ी पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ पांच राउंड फायर झोंक दिया। इस घटना में गाड़ी बाडी छलनी हो गई, लेकिन गनीमत रही कि गाड़ी में सवार युवक व उनकी मां बाल-बाल बच गए।

पीड़ित का कहना है कि एक दिन पहले अनजान व्यक्ति ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी। युवक ने गांव के ही दो युवकों व उनके साथियों पर हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कराया है। बेलघाट थाना पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

घटना शुक्रवार रात करीब आठ बजे की है, जब बहादुरपुर (थाना बेलघाट) निवासी धीरज प्रताप सिंह अपनी मां के साथ थार गाड़ी से गोरखपुर जा रहे थे। ग्राम पंचायत सोमवापुर के पास एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 33 पर बाइक सवार चार हमलावरों ने चलती गाड़ी को निशाना बनाकर गोलियां बरसाईं।

दो हमलावरों ने मुंह पर गमछा बांध रखा था और पीछे बैठे उनके साथियों फायरिंग शुरू कर दी।धीरज प्रताप सिंह का कहना है कि गुरुवार को उन्हें अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी मौखिक जानकारी थाने पर दी गई थी।

थानाध्यक्ष ने सतर्कता की सलाह भी दी थी, लेकिन अगले ही दिन हमला हो गया। धीरज की गाड़ी में चार राउंड गोली विंडशील्ड और दरवाजे पर लगी जिसकी वजह से छेद हो गए।घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष बेलघाट विकास नाथ मौके पर पहुंचे और थार गाड़ी को थाने ले आए।

एसपी दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही दो युवकों ने पुरानी रंजिश में अपने साथियों संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।आरोपितों की तलाश चल रही है।

ग्राम प्रधान की पत्नी निकली लुटेरी गैंग की सरगना, धार्मिक आयोजनों को बनाते थे निशाना

कानपुर, एजेंसी। पनकी धाम मंदिर से महिलाओं के मोबाइल और चेन लूटने वाली महिला गिरोह का राजफाश हो गया है। छह महिलाओं को हिरासत में लेकर पनकी थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लुटेरी गिरोह की सरगना गोरखपुर के कैंपियरगंज थानाक्षेत्र के एक गांव के प्रधान की पत्नी है। इस काम में उसका बेटा, बहू और अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। प्रधान की दूसरी पत्नी की भी संलिप्तता सामने आ रही है। प्रधान और उसकी दूसरी पत्नी से भी पूछताछ हो रही है। फिलहाल, पुलिस ने आरोपितों की पहचान उजागर नहीं की है।

पनकी धाम मंदिर में मंगलवार को एक साथ कई महिलाओं और युवतियों की चेन, मोबाइल और पर्स लूट लिए गए थे। महिलाओं ने पनकी धाम चौकी में शिकायत की तो पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे सीसी कैमरों को खंगाला। इनमें कुछ संदिग्ध महिलाओं की पहचान हुई। यह एक गिरोह की तरह कार्य कर रहा था और वारदात को अंजाम देने के बाद

दूसरी जगह चला गया। पुलिस ने साइबर क्राइम की टीम के सहयोग से गिरोह का पता लगाया तो इसमें शामिल महिलाएं गोरखपुर और संत कबीरनगर की रहने वाली निकलीं। उनके पूरे गिरोह का पता लगाया जा रहा है। डीसीपी पश्चिम आरती सिंह ने बताया कि अभी गिरोह के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। आरोपित महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कैंपियरगंज थानाक्षेत्र के एक गांव के प्रधान की दो पत्नियों का नाम सामने आया है। एक गिरोह की सरगना है, जबकि दूसरी की संलिप्तता की जांच चल रही है। सरगना की बहू की भूमिका भी तलाशी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गिरोह संगठित तरीके से कार्य करता है। इसकी नजर धार्मिक आयोजनों पर रहती है। हर वारदात से पहले उस शहर में होने वाले धार्मिक आयोजनों की जानकारी जुटाता है। कानपुर से पहले गिरोह लखनऊ होकर आया है। ऐसे में वहां की पुलिस से जानकारी हासिल की जा रही है। आरोपित कुंभ मेले, काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या धाम भी होकर आई हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पांच न्यायिक अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

प्रयागराज, एजेंसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पांच न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। महानिबंधक राजीव भारती की ओर से जारी सूचना के अनुसार, बलराम पंवार सिविल जज जूनियर डिवीजन सिकंदरा राऊ (हाथरस) बहाली के उपरांत भदोही के ज्ञानपुर में मो. शाहनवाज अहमद सिद्दीकी की जगह स्थानांतरित किए गए हैं।

मोहम्मद शाहनवाज अहमद सिद्दीकी सिविल जज (जूडि) भदोही, ज्ञानपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भदोही, ज्ञानपुर बनाए गए हैं। उन्हें सृष्टि पांडेय के स्थान पर नियुक्त किया गया है। सृष्टि पांडेय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भदोही यहीं अतिरिक्त सिविल जज, (जूडि) होंगी।

शिंजिनी यादव, अपर सिविल जज (जूडि) भदोही, ज्ञानपुर को यहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पद पर नियुक्त किया गया है। कमलेश कुमारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भदोही ज्ञानपुर अपर सिविल जज (जूडि) भदोही होंगी।

उधर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद (एचसीबीए) ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को गुपचुप तरीके से शनिवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए जाने की निंदा की है। साथ ही पत्र भेज कर मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली से आग्रह किया है कि उन्हें (न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को) कोई प्रशासनिक या न्यायिक दायित्व न सौंपा जाए।

महामंत्री विक्रांत पांडेय के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि पूरा बार एसोसिएशन इस जानकारी से व्यथित है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पद की शपथ 'गुपचुप' दिला दी गई।

वाराणसी रोपवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 15 किलो तक सामान ले जा सकेंगे निशुल्क

वाराणसी, एजेंसी। देश की पहली रोपवे अर्बन ट्रांसपोर्ट सुविधा को आम आदमी के लिए मुफीद बनाने की कोशिश है ताकि समाज के हर वर्ग को प्रोजेक्ट का लाभ मिले। एनएचएलएमएल (नेशनल हाईवे लाजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड) ने मोनोकेबल डेटाचेबल गोंडोला (केबल कार) और स्टेशनों पर यात्रियों के सुरक्षित लगेज प्रबंधन पर काम शुरू किया है।

तय हुआ है कि गोंडोला पर यात्री अपने साथ केवल 15 किलोग्राम तक सामान ही निश्शुल्क ले जा सकेंगे। अधिक वजन होने पर अतिरिक्त धनराशि चुकानी होगी। अतिरिक्त वजन के हिसाब से सीट का किराया निर्धारण होगा। हवाई सफर में कुछ इसी व्यवस्था से लगेज प्रबंधन हो रहा है, अब यही सिस्टम रोपवे में भी प्रभावी किया जाएगा। कैंट रोपवे स्टेशन पर एक क्लोक रूम (सामान रखने का स्थान) भी बनाया जा रहा है, यहां पर भी सामानों को सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी।

यात्रियों को टोकन के जरिए व्यवस्था मिलेगी। प्रति किलोमीटर 10 से 15 रुपये सीट का किराया निर्धारण करने की तैयारी है, इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया है। कैंट से रथयात्रा तक करीब सवा दो किलोमीटर रोपवे की एलाइनमेंट जांच और टेस्ट रन करीब डेढ़ महीने

से चल रहा है।

यात्रियों को बैठाकर ट्रायल रन करने में रोपवे कितना तैयार है, इसके लिए 28 अप्रैल को रोपवे लाइन की वृहद जांच की जाएगी। आस्ट्रिया की लाइटमर कंपनी को सुरक्षा की जांच करने की जिम्मेदारी मिली है। उनकी रिपोर्ट पर ही रोपवे को जनता के हवाले किया जाएगा।

सेक्शन एक में कैंट पर 90 जबकि रथयात्रा में 48 गोंडोला रखा जाएगा। दोनों स्टेशनों के ऊपरी तल पर बड़ा गैराज बनाया गया है, यहीं पर गोंडोला की पार्किंग की जाएगी। एक साथ 148 गोंडोला का मूवमेंट होगा, लेकिन उनका उपयोग काफी हद तक ट्रैफिक पर निर्भर रहेगा।

विशेष स्थान या सेवा की मांग सबसे अधिक होने पर गोंडोला का परिचालन बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। एनएचएलएमएल ने अगले महीने रोपवे की सुविधा जनता को सुपुर्द करने की तैयारी की है, इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा है। कहा है कि वह अपनी तरफ से परियोजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

गोदौलिया पर गतिरोध बरकरार, सिर्फ तीन सौ वूर्ग मीटर में काम

गोदौलिया में रोपवे का अंतिम स्टेशन बनाने को लेकर धीमी गति जारी है, क्योंकि यहां पर जमीन का विवाद है। प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन है। प्रशासनिक स्तर पर मामले का हल निकाला जा रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से स्टेशन निर्माण के लिए सिर्फ 300 वर्ग मीटर जमीन ही मिल सकी है, इतने हिस्से में पाइलिंग का कार्य चल रहा है। सात पाइल हो चुका है। विवादित जमीन भी एनएचएलएमएल को आवंटित हो जाएगी तो प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल सकती है।

एनएचएलएमएल ने हैदराबाद की कंपनी विश्वसमुद्र से प्रोजेक्ट निर्माण, रखरखाव व संचालन के लिए अनुबंध किया गया था। करीब सवा आठ सौ करोड़ रुपये में परियोजना दो चरणों में पूरी करनी है। यह कार्य मई 2025 तक पूर्ण होना था, लेकिन अक्टूबर तक कार्य अवधि बढ़ेगी।

पहला चरण कैंट, काशी विद्यापीठ व रथयात्रा जबकि दूसरा चरण गिरिजाघर व गोदौलिया तक है, पहले चरण का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है लेकिन दूसरे सेक्शन में बहुत काम बाकी है। अनुबंध के मुताबिक कार्यदायी कंपनी को पहले और दूसरे चरण का ट्रायल रन एक साथ करना है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाना बाकी है कि ट्रायल रन कितने चरण में किया जाना चाहिए।

फिल्म फौजी पर आया अपडेट, फिर साथ नजर आएगी प्रभास के साथ इस अभिनेत्री की जोड़ी

पैन इंडिया स्टार प्रभास इन दिनों अपनी कई आगामी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच उनकी एक और फिल्म फौजी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस फिल्म में प्रभास की जोड़ी उनकी फिल्म कल्कि 2898 एडी की एक अभिनेत्री के साथ नजर आएगी। क्या आप बता सकते हैं कि वह अभिनेत्री कौन हैं...

फौजी में नजर आएगी दिशा के साथ प्रभास की जोड़ी

एक खबर के मुताबिक, फौजी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फौजी में प्रभास और दिशा पाटनी एक साथ नजर आ सकते हैं। इस फिल्म से पहले प्रभास और दिशा की जोड़ी को प्रशंसकों ने कल्कि 2898 एडी में खूब पसंद किया था। बहरहाल, इस फिल्म का आधिकारिक नाम अभी तक तय नहीं हुआ है, तब तक इस फिल्म का संभावित नाम फौजी है।

फिल्म में होंगी दो अभिनेत्रियां

वैसे इस फिल्म में दो अभिनेत्रियों के होने की बात सामने आई है, जिसमें इमानवी इस्माइल का नाम पहले से ही शामिल है और अब उनके अलावा इस फिल्म में दूसरी मुख्य अभिनेत्री के तौर पर दिशा पाटनी का नाम शामिल हो गया है। बहरहाल, अभी तक निर्माताओं की ओर से इस फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फौजी के अलावा साउथ अभिनेता प्रभास स्पिरिट, द राजा साब के अलावा भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे। स्पिरिट का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास एक पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, द राजा साब एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है।

स्त्री 2 के बाद रेड 2 में आइटम नंबर करेंगी तमन्ना भाटिया, यो यो हनी सिंह भी बनेंगे गाने का हिस्सा

रेड 2 अपने एलान के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज की तारीख के साथ-साथ रेड 2 के कलाकारों के भी लुक साझा किए थे। फिल्म के टीजर ने भी दर्शकों के बीच काफी उत्साह पैदा किया था, जिसके बाद से दर्शकों को बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार है। इस बीच अब फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है।

रेड 2 में सीधे-सादे आईआरएस अधिकारी अमय पटनायक की अपनी भूमिका को दोहराने के लिए तैयार हैं। निर्माता एक खास प्रमोशनल नंबर के साथ इसे और भी मसालेदार बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, तमन्ना भाटिया को रैपर यो यो हनी सिंह के साथ एक हाई-एनर्जी डांस ट्रैक के लिए साइन किया गया है। विजय गांगुली द्वारा कोरियोग्राफ किया गया यह गाना इस सप्ताह मुंबई के एक स्टूडियो में दो दिनों में फिल्माया जाएगा।

तमन्ना और विजय की फिल्म यह गाना एक स्टैंडअलोन पोस्ट-क्रेडिट के रूप में काम करेगा। हालांकि, अजय

और तमन्ना इस ट्रैक में स्क्रीन स्पेस साझा नहीं करेंगे। बता दें कि अजय और तमन्ना इससे पहले ही रेंजर पर एक साथ काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन मिशन मंगल के जगन शक्ति ने किया है। उम्मीद है कि इस नंबर की शूटिंग खत्म होने के बाद तमन्ना रेंजर के सेट पर शामिल होंगी।

फिल्म की कहानी और कलाकार

राज कुमार गुप्ता द्वारा निर्देशित और रितेश शाह, करण व्यास और जयदीप यादव सहित और टीम द्वारा लिखित रेड 2 अमय पटनायक की 75वीं छापेमारी पर आधारित है। इस बार छापमारी दादा भाई नाम के एक शक्तिशाली टाइकून के खिलाफ होगी, जिसका किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर, रजत कपूर, सुप्रिया पाठक, अमित सियाल और यशपाल शर्मा भी हैं। सौरभ शुक्ला सीतागढ़ के खूंखार डॉन ताऊजी की अपनी भूमिका को फिर से दोहराएंगे।

एकता कपूर ने नागिन 7 पर लगाई मुहर

एकता कपूर ने अपने प्रसिद्ध नागिन सीरियल के सातवें सीजन की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी है। एकता ने नागिन 7 को लेकर एर दिलचस्प जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करके फैंस को खुश कर दिया है।

कब आएगा नागिन 7

ईद के खास मौके पर एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में एकता अपनी टीम के साथ कुछ खास बात करती नजर आईं। एकता ने इंस्टाग्राम वीडियो में कहा, यह ईद है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुझे सभी को ईदी देनी है। आगे एकता ने कहा, नागिन 7 जल्द आएगा, बहुत जल्द। एकता के इस वीडियो ने फैंस की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया है।

ईशा मालवीय हो सकती हैं अगली नागिन

एक खबर के मुताबिक, एकता के नागिन 7 में इस बार ईशा मालवीय नागिन के रोल में नजर आ सकती हैं। उडारियां और बिग बॉस 17 से प्रसिद्ध हुईं ईशा अगर नागिन 7 में आती हैं, तो यह उनके करियर के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी।

नागिन सीरियल की शुरुआत

एकता कपूर के प्रसिद्ध नागिन सीरियल का पहला सीजन 2015 में शुरू हुआ था, जिसमें मौनी रॉय, अदा खान और अर्जुन बिजलानी ने अपने शानदार अभिनय से दर्शको का दिल जीता था। पहले सीजन की सफलता के बाद इसके अभी तक छह सीजन आ चुके हैं। अब प्रशंसकों को नागिन 7 के आने का इंतजार है।

नागिन सीरियल ने कई अभिनेत्रियों को दिलाई पहचान

नागिन टीवी सीरियल ने कई चेहरो को फैंस के बीच खास बनाया, जिनमें मौनी रॉय से लेकर हिना खान, अदा खान, सुरभि ज्योति, सुरभि चंदना, तेजस्वी प्रकाश और रश्मि देसाई शामिल हैं। बहरहाल, फैंस को अब नागिन 7 के आने का बेसब्री से इंतजार है।

तुम्बाड़ फेम निर्देशक के साथ काम करने जा रहीं हैं श्रद्धा

श्रद्धा कपूर ने हाल ही में हॉरर-कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 से दर्शकों का दिल जीता था। इसके बाद से उन्होंने अपनी अगली फिल्म की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। हालांकि, अब खबर आ रही है कि श्रद्धा जल्द ही तुम्बाड़ के निर्देशक राही अनिल बर्वे के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली हैं। इस फिल्म का निर्माण एकता कपूर करेंगी।

तुम्बाड़ के निर्देशक के साथ करने जा रहीं काम

हालांकि, अभी इसकी कहानी और नाम का खुलासा नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा और एकता कपूर कई फिल्मों को लेकर बातचीत कर रही हैं। इनमें से एक हाई-कॉन्सेप्ट थ्रिलर फिल्म है, जिसे तुम्बाड़ फेम निर्देशक राही अनिल बर्वे ने तैयार किया है।

श्रद्धा को पसंद आई फिल्म की कहानी रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और श्रद्धा इसकी अनोखी कहानी से बेहद प्रभावित हैं। उन्हें लगता है कि यह अनाम थ्रिलर स्त्री 2 के बाद उनके लिए एक शानदार फिल्म हो सकती है। श्रद्धा इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं।

लव स्टोरी फिल्म पर भी चल रही चर्चा इसके अलावा श्रद्धा एकता कपूर के साथ एक लव स्टोरी पर भी चर्चा कर रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन आशिकी 2 फेम निर्देशक मोहित सूरी करेंगे। खास बात यह है कि इसमें श्रद्धा की जोड़ी एक बार फिर आदित्य रॉय कपूर के साथ नजर आ सकती है। सूत्रों का कहना है कि श्रद्धा के पास कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स अभी गुप्त रखी गई हैं।

नागिन ट्रिलॉजी की तैयारी में जुटी हैं अभिनेत्री

इन सबके बीच श्रद्धा कपूर नागिन ट्रिलॉजी की तैयारी में भी जुटी हैं। यह एक मेगा-बजट फिल्म है, जिसका निर्देशन विशाल फुरिया कर रहे हैं। इसमें श्रद्धा मुख्य किरदार नागिन के रूप में दिखेंगी। खास बात यह है कि इस फेंचाइजी में वीएफएक्स का भारी इस्तेमाल होगा, जिससे दर्शकों को कुछ अलग देखने को मिलेगा।

कॉमेडी करते-करते कैसे खूंखार विलेन बने राघव जुयाल

आईफा 2025 में फिल्म 'किल' के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल का अवॉर्ड जीतने वाले अभिनेता राघव जुयाल ने हाल ही में खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री में हर तरह के किरदार निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही राघव ने बताया कि वो अपने किरदारों के लिए कैसे तैयारी करते हैं। बातचीत में फिल्म 'किल' के अपने किरदार के बारे में बात करते हुए राघव ने कहा, मेरा मानना है कि कोई भी किरदार आए, एक्टर को उस किरदार में घुस जाना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। इससे धीरे-धीरे वो किरदार में ढलने लगता है और उसे अपने किरदार की समझ आने लगती है। जो बाद में रोल को असरदार बनाने में मददगार साबित होता है।

मैं सभी ऑफर ठुकरा रहा हूं

बॉलीवुड में अक्सर जब किसी अभिनेता का एक किरदार हिट हो जाता है तो फिर उसे एक जैसे रोल ऑफर होने लगते हैं। टाइपकास्ट होने के डर पर बात करते हुए राघव ने कहा, मैं एक जैसे सभी ऑफर ठुकरा रहा हूं। मैं हर बार कुछ अलग और नया करना चाहता हूं। मैं एक जैसे किरदार बार-बार नहीं निभाना चाहता।

एक जैसे किरदार नहीं करूंगा

राघव ने आगे कहा, अगर आप मेरी जर्नी देखें तो मैंने बैक डांसर के तौर पर शुरूआत की, फिर मैं डांसर बना। उसके बाद मैंने शो होस्ट किया और अब एक्टिंग कर रहा हूं। जब मैं इंडस्ट्री में रहकर इतने प्रोफेशन बदल चुका हूं, तो मैं एक जैसे किरदार तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा।

'किल' के किरदार के लिए की काफी मेहनत

अब तक चुलबुले अंदाज में दिखने वाले राघव ने इतने खतरनाक विलेन की भूमिका कैसे निभाई? पूछा जाने पर राघव कहते हैं- मुझे खुद नहीं पता कैसे हुआ, बस हो गया। मैंने बस अपने किरदार पर काफी काम किया, काफी मेहनत की। शायद उसी मेहनत का नतीजा है कि ये हो गया।

सफल रही थी 'किल'

साल 2024 में आई फिल्म 'किल' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में काफी हिंसक एक्शन दिखाया गया है। फिल्म में राघव जुयाल ने 'फनी' नाम के किरदार की भूमिका निभाई है, जो फिल्म का खलनायक है। निखिल नागेश भट द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राघव के अलावा लक्ष्य, तान्या मानिकतला, आशीष विद्यार्थी, अद्रिजा सिन्हा, हर्ष छाया और अभिषेक चौहान प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी।

टेस्ट की रिलीज से पहले 'टॉक्सिक' की शूट के लिए मुंबई पहुंचीं नयनतारा?

साउथ अभिनेत्री की फिल्म 'टेस्ट' 4 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगी। इस बीच अभिनेत्री को मुंबई में एयरपोर्ट पर देखा गया। दरअसल, नयनतार 'केजीएफ' फेम अभिनेता यश गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक' का हिस्सा हैं। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में हो रही है। संभवत: अभिनेत्री इसी के सिलसिले में वहां पहुंची हैं। हालांकि, फिल्म से अभिनेत्री की भूमिका के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका किरदार एक गेम चेंजर होगा। फिल्म में कियारा आडवाणी फीमेल लीड हैं, उनके साथ हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और अक्षय ओबेरॉय भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 'टॉक्सिक' को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के बड़े बजट में बनाया जा रहा है। फिल्म को अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में 19 मार्च 2026 में रिलीज किया जाएगा।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक पीतम सिंह द्वारा कोमल प्रिंटर्स चौधरी मार्केट मोरना, सेक्टर-35 नोएडा गौतमबुद्धनगर से छपवाकर मकान नं0.57 ग्राम सौरखा जाहिदाबाद सेक्टर-115 नोएडा गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 से प्रकाशित किया। RNI.NO.UPHIN/2010/31600
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदाई। सभी विवादों के न्याय गौतमबुद्धनगर (**संपादकः प्रमोद यादव**) न्यायालय के अधीन होगा। M-9999164275,editorsaimedia@gmail.com